RNI No. UPHIN/2000/3766 ISSN No. 2581-3528 | ₹:20

केशव संवाद

आश्विन-कार्तिक विक्रम सम्वत् 2078 (अक्टूबर -2021)

- आस्था का हुआ सम्मान
- बेमिसाल कोरोना प्रबन्धन
- चुनौतियों को अवसर में बदलता उत्तर प्रदेश
- संकल्प से सिद्धि करता उत्तर प्रदेश

सफाई, दवाई और कड़ाई
जीतेंगे कोरोना से लड़ाई

- मास्क अवश्य पहनें।
- दो गज़ की दूरी का पालन करें।
- सैनिटाईजर/साबुन से बार-बार हाथ साफ करें।
- खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने पर जाँच कराऐं।

कोरोना की जाँच एवं उपचार सरकारी चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपलब्ध है।

45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक टीकाकरण अवश्य करवाएं।

#Unite2FightCorona

दो गज़ की दूरी मास्क है जरूरी

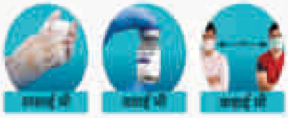

हेल्पलाइन नं. **104**

घबराने की नहीं है बात सरकार खड़ी है साथ

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

अक्टूबर, 2021

वर्ष : 21 अंक : 10

प्रबंध निदेशक
अणंज कुमार त्यागी

संपादक
कृपाशंकर

केशव संवाद पत्रिका प्रमुख
डॉ. प्रियंका सिंह

अंक संपादक
डॉ. नीलम कुमारी

संपादक मंडल
डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. अखिलेश मिश्र

पृष्ठ संयोजन
वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301
फोन नं. 0120 4565851, 2400335
ईमेल : keshavsamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.prernanews.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन 105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

जेवर एयरपोर्ट आर्थिक समृद्धि के लिए मील का पत्थर –डॉ. अनिल निगम..........05

ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजता उत्तर प्रदेश – प्रो. आराधना.................06

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं महिलाओं की भूमिका – अनुपमा जायसवाल...08

उत्तर प्रदेश की पहल जनसंख्या नियंत्रण कानून – डॉ. प्रदीप कुमार.............10

उत्तर प्रदेश में राम गमन पथ और आर्थिक विकास – प्रो. हरेन्द्र सिंह...............12

एक जिला – एक उत्पाद – अनुपमा अग्रवाल........14

इथेनाल उद्योग एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश – डॉ. अखिलेश मिश्र.......16

मुजफ्फरनगर में गुड़ उद्योग सीमित संसाधन... – चन्द्रभूषण सिंह.............18

संकल्प से सिद्धि करता उत्तर प्रदेश – डॉ. उर्विजा शर्मा...........19

सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के पटल पर अयोध्या – डॉ. प्रियंका सिंह...........20

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में युवाओं का योगदान – डॉ. राहुल त्यागी...........21

उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में... – डॉ. अंशु जोशी..............22

उत्तम प्रदेश बनता उत्तर प्रदेश – डॉ. नीलम कुमारी.........24

आत्मनिर्भरता को पंख लगाता विदेशी निवेश – नेहा कक्कड़...................26

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और किसान – डॉ. यशवीर सिंह..........28

प्रशासनिक व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में... – अनीता चौधरी............30

चुनौतियों को अवसर में बदलता उत्तर प्रदेश – डॉ. शशि शर्मा............32

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया, 'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail-com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

ISSN No. 2581-3528

संपादकीय...

मनुस्मृतिः में कहा गया है कि, "सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ||" अर्थात जो कार्य दूसरे के वश में होता है वह सदैव मनुष्य को दुख प्रदान करता है और जो कार्य स्वयं अपने वश में होता है अथवा अपने नियन्त्रण में होता है वह सदैव सुख देने वाला होता है। और मनुस्मृतिः के इसी श्लोक को आज उत्तर प्रदेश चरितार्थ कर रही है।

आत्मनिर्भर होना या स्वावलंबी होना किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के विकास की प्रथम अनिवार्य शर्त है। यही कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत कोरोना जैसे संकट काल मे भी संगठित क्षेत्र में रोजगार देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया था।

भारतीय संस्कृति व धर्म के मूल आधार स्तंभ भगवान श्रीराम एवं कृष्ण व सम्राट भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पडा, की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदी साहित्य के सूर्य और शशि महाकवि सूरदास तथा तुलसीदास की तपोभूमि है, महारानी लक्ष्मी बाई जैसी वीरांगना की गौरव गाथा और स्वतंत्रता सेनानियों की समरभूमि है, महर्षि बाल्मीकि व देवऋषि वेदव्यास की देवभूमि है, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम है, बौद्ध व जैन धर्म की कर्मस्थली है। जहां पिछली सरकारों के शासन काल में ऐसे सांस्कृतिक विरासत वाले, भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले व देश का सबसे बड़ा राज्य कहलाने वाले राज्य में अव्यवस्था, गुंडाराज व भ्रष्टाचार पनपा और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाने लगा तथा उत्तर प्रदेश को देश के विकास को अवरुद्ध करने वाले राज्य की संज्ञा दी जाने लगी। वहीं दूसरी ओर अब आदरणीय मोदी जी व माननीय योगी जी के अथक प्रयासों ने उत्तर प्रदेश के माथे से बीमारू राज्य का टीका हटाकर समृद्धि शीलता का टीका लगा दिया है। और आज हम देख रहे है उत्तर प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार व परिवहन जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है।

वर्तमान सरकार ने जिस तरह से आत्मनिर्भरता को पंख लगाने के लिए विकास की गति को आगे बढ़ाया उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की योजनाओं में अग्रणी है। आज भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। जगमग गांव, लहलहाते खेत, निश्चिंत महिलाएं, उत्साही युवा, उत्सुक उद्यमी व चमचमाती सड़कें स्वयं ही विकास की कहानी कहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने से आज उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के लोगों की धारणा बदली है। सुरक्षा व सुशासन होने से बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग में पहले उत्तर प्रदेश14 वें स्थान पर था जो कि 2020 में ही उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है, इस प्रकार वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नही छोड़ी है। ऐसा लगता है कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज देश और दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है और उत्तर प्रदेश उद्योगपतियों, पूंजी निवेशकों कॉरपोरेट सेक्टरों का सर्वप्रिय राज्य बन गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के इन्ही विभिन्न पहलुओं को अपने में समाये केशव संवाद पत्रिका के अक्तूबर माह का यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विशेषांक आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा है कि प्रस्तुत विशेषांक भारत के आत्मनिर्भर सपने को साकार करने व माँ भारती को परम वैभव पर ले जाने के लिए दृढसंकल्पित, कृतसंकल्पित भारतवासियों व सुधि पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा ।

परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं।

समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्।।

इसी भाव के साथ

डॉ. नीलम कुमारी
अंक संपादिका

ISSN No. 2581-3528

मंथन

आर्थिक समृद्धि के लिए मील का पत्थर जेवर एयरपोर्ट

डॉ. अनिल निगम
डीन, पत्रकारिता तथा जनसंचार विभाग
आईआईएमटी कॉलेज, ग्रेटर नोएडा

जेवर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बनने से गौतमबुद्ध नगर जिले की ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। इसके बनने से देशभर के सात लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने के साथ–साथ प्रदेश का चहुंमुखी विकास होना तय है। एयरपोर्ट के आस–पास लगने वाले उद्योगों, फिल्म सिटी और होने वाले सर्वांगीण विकास के चलते यह निर्णय प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में ''मील का पत्थर'' साबित होगा।

जेवर एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 80 किलोमीटर दूर गौतमबुद्धनगर जिले के जेवर में बन रहा है। उल्लेखनीय है कि जेवर हवाई अड्डे का निर्माण स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ZIA) एजी के द्वारा किया जायेगा। इसके निर्माण में 29,560 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आने की संभावना है।

गौरतलब है कि नोएडा औद्योगिक शहर की स्थापना 17 अप्रैल 1976 में और ग्रेटर नोएडा की वर्ष 1997 में की गई। इन दोनों ही शहरों की स्थापना का उद्देश्य यहां पर छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों का विकास करना रहा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक औद्योगिक निवेश के लिए 24 अप्रैल, 2001 को यमुना प्राधिकरण का भी गठन किया। इस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा को प्रदेश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों ही शहरों को देश के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने के उद्देश्य से कई प्रयत्न किए हैं। उसने यमुना एक्सप्रेस के साथ फिल्म सिटी, औद्योगिक शहरों और रिहायशी शहरों को बसाने का काम तेज कर दिया है। विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से ही जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।

जेवर में बनने वाले इस हवाई अड्डे को नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश की जिस लोकेशन पर यह एयरपोर्ट बन रहा है, वह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों इस एयरपोर्ट के नामकरण, लोगो व डिजाइन को अंतिम रूप प्रदान कर दिया। मुख्यमंत्री को यह उम्मीद भी जताई है कि यह एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में बनकर उभरेगा। एयरपोर्ट के बनकर चालू होने के बाद यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाला देश का बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। योजना के अनुसार, अगर वर्ष 2023 में उड़ान शुरू होती है तो सातवें साल में 1.6 लाख करोड़ रुपये का सालाना राजस्व मिलने लगेगा।

यह हवाई अड्डा चार वर्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ–साथ दिल्ली और हरियाणा की किस्मत भी बदलने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि हवाई अड्डा बनने के बाद यहां पर सात लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसका लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के निवासियों को मिलेगा। वास्तविकता यह है कि केवल एयरपोर्ट में एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा जबकि इसके आस–पास काम करने वाले लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। चूंकि इस एयरपोर्ट से करीब 50 लाख यात्रियों के हर वर्ष सफर करने का आकलन है। इसलिए यहां पर रोजगार की संभावनाएं 10 लाख से अधिक भी जा सकती हैं।

देश के सभी नागरिकों के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात यह है कि इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के साथ इस क्षेत्र की पूरी तरह से तस्वीर बदलने वाली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यमुना प्राधिकरण सिटी में अब तक 126 उद्योगपति धंधों के लिए जमीन आवंटित करा चुके हैं। एयरपोर्ट के आसपास टैक्सटाइल उद्योग की 100 से अधिक इकाइयों ने यमुना प्राधिकरण से यहां पर अपने उद्योग लगाने के लिए जमीन के लिए आवेदन करने की इच्छा जताई है। औद्योगिक संभावनाओं के मद्देनजर यहां पर 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है। विकास को पंख लगाने के उद्देश्य से ही एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से दिल्ली से होते हुए नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ने की योजना है। हाई स्पीड रेल की कुल लंबाई 816 किलोमीटर है, जो औसतन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यही नहीं, नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी संचालित करने की योजना है। यह देश की पहली पॉड टैक्सी होगी। यह ऑटोमेटिक गाड़ी है, जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। पॉड टैक्सी कॉरिडोर की लंबाई 14.6 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर 862 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह मेट्रो ट्रेन के मुकाबले कम खर्चीला है।

लंबे अरसे से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर खबरें आती रही हैं। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होते ही फिल्म सिटी का सपना भी पूरा होने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी बनने से यहां पर फिल्म, टीवी और अन्य कला क्षेत्र से जुड़े लोगों का आवागमन सहज हो जाएगा। इसके अलावा, एयरपोर्ट के बनने से यहां पर मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं व्यवसाय संबंधी अनेक संस्थानों के खुलने की संभावनाएं बन जाएंगी।

जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से दिल्ली–एनसीआर ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों को इस एयरपोर्ट के माध्यम से सीधी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। इसे यमुना एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के कारण यह ताजनगरी आगरा सहित प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए गेटवे का काम करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनकर चालू होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव घटेगा। वस्तुतः एयपोर्ट के निर्माण से देश के लगभग सात लाख युवाओं को रोजगार तो मिलेगा साथ ही यह देश और राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाने में अत्यंत भूमिका भी निभाएगा।

ISSN No. 2581-3528

प्रो. आराधना
प्रोफेसर, इतिहास विभाग
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजता उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश जनसंख्या, राजनैतिक, जागरूकता, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत व स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य रहा है। यहां का इतिहास शांति–पूर्ण सह अस्तित्व का इतिहास है। यहां बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिक्ख व सनातनधर्मी अनुयायी एक साथ रहे और एक–दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन को प्रभावित व समृद्ध करते रहे। विविधता में एकता तथा ''जियो और जीने दो'' का व्यवहारिक स्वरूप यहां की पहचान है। यहां धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत से स्थान है साथ ही बहुत से ऐसे स्थल भी है, जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजे हैं यथा –

भीतरगांव – कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील में कानपुर से लगभग 32 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। यहां गुप्त कालीन ईंट का बना हुआ एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है।

प्रयाग (इलाहाबाद) – यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। लगभग प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ में प्रयाग का उल्लेख मिलता है। यहां हर 12 वें वर्ष कुम्भ और हर छठें वर्ष अर्द्ध कुम्भ का मेला लगता है। भारद्वाज मुनि का आश्रम तथा प्राचीन अक्षयवर भी यहीं है। प्रयाग, गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है तथा 'तीर्थराज' के नाम से भी जाना जाता है। संगम पर एक किला है, जिसे अकबर ने बनवाया था। संगम पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी है। कहते है कि मां गंगा स्वयं उनका अभिषेक करने आती हैं।

सोरों (जिला एटा) – सोरो या शूकर क्षेत्र की गणना भारत के पवित्र तीर्थों में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में पृथ्वी का आविर्भाव यहीं हुआ था यहां वराह भगवान का एक अति प्राचीन दर्शनीय मंदिर है। जिसमें भगवान वराह की विशाल प्रतिमा स्थापित है। प्राचीन काल से ही यहां वराह भगवान की पुण्य–स्मृति में मार्गशीर्ष का मेला लगता है।

काशी (वाराणसी)– यह भारत ही नहीं अपितु संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक हैं। वाराणसी नाम वरूणा और अस्सी दो नदियों से मिलकर बना है। यहां काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर, आदि विश्वेश्वर, साक्षी विनायक आदि दर्शनीय मंदिर है। कुण्डों तथा वापियों में दुर्गा कुण्ड, पुष्कर कुण्ड, पिशाच मोचन, कपिलधारा, मानसरोवर तथा मंदाकिनी उल्लेखनीय हैं। यहां 84 घाट हैं जिनमें अस्सी तुलसी, हरिश्चन्द्र, अहिल्याबाई, दशाश्वमेघ तथा मणिकार्णिका घाट आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। शाम के समय नाव पर बैठकर गंगा की आरती का दर्शन करने विदेशी भी बड़ी संख्या में प्रतिदिन यहां आते हैं।

सारनाथ – बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने मृगदाव (सारनाथ) में आकर अपना धर्मोपदेश दिया था। यहां खुदाई में अनेक प्राचीन विहारों और मंदिरों के भग्नाविशेष प्राप्त हुए हैं। यहां का धामेख स्तूप जगप्रसिद्ध है। साथ ही यहां का पुरातत्व संग्रहालय भी दर्शनीय है।

शाकुम्भरी देवी (सहारनपुर) – सहारनपुर से 41.5 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके पास ही देव कुण्ड सरोवर है। यहां नवरात्रि में मेला लगता है।

हस्तिनापुर (मेरठ) – मेरठ से 35.2 किमी. दूर यह नगरी पांडवों की राजधानी थी। कार्तिक पूर्णिमा को यहां बड़ा मेला लगता है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी को राजा श्रेयांस ने यहीं इक्षुरस का दान दिया था। इसलिए इसे 'दानतीर्थ' कहा जाता है। यहां के जम्बूदीप जैन मंदिर के दर्शन हेतु वर्ष पर्यन्त लोग आते रहते हैं। स्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों के मंदिर यहां है। साथ ही

पाण्डवों का टीला (जिसकी प्रो. बी. लाल ने 1952 में खुदाई कराकर, बहुत सी पुरातात्विक वस्तुऐं प्राप्त की थी), पांडव मंदिर, विदुर टीला, बारादरी, द्रोणेश्वर मंदिर, कर्ण मंदिर, द्रोपदी घाट, कामा घाट आदि महत्वपूर्ण व दर्शनीय स्थल हैं।

कुशीनगर – पडरौना से लगभग 19 किमी. दूर है। वर्तमान कसया नगर के पास स्थित है। भगवान बुद्ध ने यहां निर्वाण प्राप्त किया था। यहां खुदाई में एक प्राचीन निर्वाण स्तूप मिला है। कई गुप्तकालीन विहार और मंदिर भी उत्खनन से प्रापत हुए हैं। सर्वाधिक महत्पवूर्ण मूर्ति है बुद्ध की लेटी हुयी विशाल प्रतिमा। बुद्ध पूर्णिमा से यहां मेला प्रारम्भ होता है, जो लगभग डेढ़ माह तक चलता है।

मथुरा– इसकी गणना सप्त महापुरियों में होती है। यहां श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर और विश्राम घाट है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों लोग आते हैं।

वृंदावन – यहां लगभग 4000 मंदिर, घाट और सरोवर है। गोंविद देव मंदिर बड़ा भव्य और सुंदर है। इसके साथ ही रंगनाथ मंदिर बिहारी जी का मंदिर, राधावल्लभ जी का मंदिर, राधारमण जी का मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, शाह जी का मंदिर, अष्ट सखी मंदिर और प्रेम मंदिर जगप्रसिद्ध है। निधिवन और सेवा कुंज प्रसिद्ध वन स्थलियां हैं। वंशीघाट, कालीदह, कशघाट आदि यमुना के प्रसिद्ध घाट यहां स्थित है।

बरसाना– इसका मूल नाम ब्रहमासारिणी था। यह भगवान कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म स्थान है। यहां लाडली जी (राधा जी का स्थानीय नाम) का मंदिर है। राधाष्टमी पर यहां मेला लगता है।

बिठूर – यह ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम ब्रहमावर्त तीर्थ है। यहां महर्षि बाल्मीकि का आश्रम, सीता रसोई आदि मुख्य दर्शनीय स्थल है।

चित्रकूट – वन जाते समय श्रीराम यहां रूके थे। जनश्रुति के अनुसार बाल्मीकि ऋषि भी यहां रहे थे। मंदाकिनी नदी चित्रकूट के जंगलों से होकर बहती है। इस नदी के बांये तट पर कामतानाथ से लगभग 2.4 किमी पर सीतापुर है। जहां नदी के किनारे–किनारे 24 घाट हैं। इनमें से राघव प्रयाग, कैलाश घाट, रामघाट और घृतकल्प घाट विशेष महत्वपूर्ण हैं। सीतापुर में अनेक प्राचीन मंदिर हैं। रामघाट के समीप स्थित पर्णकुटी के विषय में कहा जाता है कि श्रीराम ने यहां निवास किया था। यहां से लगभग 30 किमी. की दूरी पर सती अनुसूया और महर्षि अत्रि का आश्रम है। एक पहाड़ी के अंचल में अनुसूया, अत्रि, दत्तात्रेय और हनुमान जी के मंदिर है। इसे मंदराचल कहते हैं। यहां से मंदाकिनी निकलती है। सीतापुर से 3.30 किमी. की दूरी पर रमणीक जानकी कुंड है। यहां नदी की धारा स्वेत पत्थरों के ऊपर से होकर बहती है। जानकी कुंड से 3.2 किमी पर स्फटिक शिला है। यहां दो बड़ी चट्टाने हैं। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने यहां विश्राम किया था। चित्रकूट में भरत कूप भी है। इस सम्बंध में एक कथा है कि श्रीराम के राजतिलक हेतु सभी पवित्र नदियों से एकत्र जल को इस कुएं में डाला गया था।

आगरा – विश्व का आश्चर्य कहा जाने वाला ताज महल जो कि सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसे देखने के लिए विश्वभर से लोग आगरा आते हैं। आगरा से 40 किमी. दूर स्थित फतेहपुर सीकरी में अकबर का बनवाया हुआ किला और महल है। अकबर का मकबरा सिकन्दरा तथा एतमादुद्दौला का मकबरा शिया संत काजी नूरूल्ला की मजार भी उल्लेखनीय है।

लखनऊ – जनश्रुति है कि यह नगर भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था। इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। यहां एक पुराना टीला है जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है। नवाब आसफुद्दौला ने यहां रूमी दरवाजा, इमामबाड़ा आसफी मस्जिद, दौलतखाना, रेजीडेंसी, बिबियापुर कोठी, आदि का निर्माण कराया। गाजीउद्दीन हैदर ने मोती महल, मुबारक मंजिल, सआदत अली का मकबरा बनवाया। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान में बनवाया गया शहीद स्मारक, चिड़ियाघर व बाटेनिकल गार्डन भी दर्शनीय स्थल है। इन सभी ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए वर्ष भर लोग यहां आते रहते हैं।

गोला गोकर्णनाथ – लखीमपुर खीरी से लगभग 35 किमी. दूर स्थित गोला गोकर्णनाथ के विषय में कहा जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे लंका में शिवलिंग, स्थापित करने को कहा था। पर शिवलिंग को ले जाते समय उसे भूमि पर रखना निषेध था। परंतु लघुशंका के चलते रावण ने उसे एक भक्त को दे दिया और भक्त शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। वापस आकर रावण बहुत क्रोधित हुआ पर अब कुछ नहीं हो सकता थां इस कथा के आधार पर इस स्थान का नाम गोला गोकर्णनाथ हुआ।

कम्पिल (फर्रूखबाद) – विष्णु पुराण, जातक कथाओं, रामायण व अनेक अन्य ग्रंथों में इस नगरी का उल्लेख है। यह स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक तेरहवें तीर्थकर भगवान विमल नाथ, महासती द्रोपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। यहां कपिलमुनि का आश्रम, रामेश्वरधाम मंदिर, जैन श्वेताम्बर मंदिर, जैन दिगम्बर मंदिर, भेदकुण्ड, अनेक छोटे मंदिर, भग्नावशेष प्राचीन कुंए आदि अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर विद्यमान हैं। जो पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों, शिल्पियों शोध–छात्रों आदि के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र है।

संकिस्सा (फर्रूखबाद) – प्राचीन काल में संकास्य नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री हेवनसांग ने इसका उल्लेख कपित्थ नाम से किया है। इसके एक टीले पर कुछ भग्नावशेष हैं। बौद्ध मतानुयायियों के अनुसार भगवान बुद्ध यहां देवलोक से अवतरित हुए थे।

कन्नौज – प्राचीन काल में कान्यकुब्ज नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री हवेनसांग के अनुसार वहां अनेक संथालय थे, जिनमें लगभग 10,000 भिक्षु रहते थे। नगर में 200 देव मन्दिर थे। जिनमें से अनेक शिव, विष्णु और देवी के मंदिर थे। यहां क्षेमकली देवी का मंदिर, पदमावती सती मन्दिर, हजारों वर्ष पुराने खण्डहर आदि है। पुरातत्व, कला और संस्कृति के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं।

गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर) :– जिस स्थान पर महायोगी गोरक्षनाथ ने खिचड़ी का प्रसाद बांटा और चमत्कार दिखाया। उसी स्थान पर गोरक्षनाथ जी का मन्दिर स्थापित है। यह महायोगी जी की तपस्थली और नाथ सम्प्रदाय का सिद्धपीठ है। प्रतिवर्ष यहां मेला लगता है।

शुक्रताल (मुजफ्फरनगर) :– जिस वटवृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य ने राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी, वहां अब एक भव्य मंदिर है। पास ही हनुमान मंदिर, नक्षत्र वाटिका व अन्य बहुत से मंदिर है। यहां भागवत कथा का आयोजन लगभग वर्षपर्यन्त होता रहता है। बड़ी संख्या में पर्यटक व श्रद्धालु यहां आते हैं।

बाराबंकी – लखनऊ से लगभग 27 किमी. की दूरी पर स्थित बाराबंकी में महादेवा, किन्तूर, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध स्थान है। जनश्रुति है कि महाराज युधिष्ठिर ने यहां महादेव की स्थापना की थी महारानी कुंती द्वारा स्थापित कुन्तेश्वर मंदिर भी किन्तूर ग्राम में है।

कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजता उत्तर प्रदेश अपने आप में विशिष्ट है। अनूठी है यहा की धरोहर...जिन्हें देखने को लोग लालायित रहते हैं।

ISSN No. 2581-3528

उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं का योगदान

अनुपमा जायसवाल
पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
विधायक, सदर बहराइच

जब हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि आत्मनिर्भरता क्या है। आत्मनिर्भर भारत के अपने विचार को देशवासियों से साझा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी हुई है। हमने ऐसा संकट ना देखा है ना ही सुना लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा लेकिन इसका मार्ग क्या है इसका एक ही मार्ग है आत्मनिर्भर भारत जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो भारत आत्मनिर्भर इकाई थी।

आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमी पैकेज दिया जो अर्थव्यवस्था और समाज के हर वर्ग को लक्षित करता है। आत्मनिर्भरता का मतलब भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से काटना नहीं है। इसके बजाय, इसका अर्थ है पांच स्तंभों, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग पर अधिक जोर देकर भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक मूल्यवान योगदानकर्ता बनाना।

इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी बिना रुके–बिना घबराए उत्तर प्रदेश के लिए अनथक योद्धा के रूप में सामने आए। बिना रुके बैठकों का दौर चलता रहा फोन और ग्राउंड निरीक्षण कर मुख्यमंत्री जी ने हालातों को परत–दर–परत जाना आत्मनिर्भर भारत के लिए योगी सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पूर्ण पालन तो कर ही रही है साथ ही एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के द्वारा वह पहले से ही वोकल फॉर लोकल के नारे को चरितार्थ कर रही है।

उत्तर प्रदेश को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए योगी जी 5.5 लाख करोड़ का बजट लेकर आए। कई योजनाएं शुरू की गईं और उन्हें अक्षरशः लागू किया गया। आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई। हमारे प्रवासी श्रमिक भाइयों के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना ने कोविड–19 के कारण राज्य में वापस लौटे श्रमिकों को स्वरोजगार और रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया। यह पहल राज्य के 31 जिलों में रोजगार के अवसर विकसित कर रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने कुल खर्च का 6.3 प्रतिशत आवंटित किया, जो राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (5.6 प्रतिशत) से अधिक है। राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य एटीएम खोले जाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्रांति आएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना छात्राओं को टैबलेट वितरित करेगी।

ISSN No. 2581-3528

कोविड की लगातार लहरों के दौरान, हमने मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में, लाखों निवासियों के जीवन और आजीविका को बचाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों प्रवासी मजदूरों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार योजना की शुरुआत की। यूपी अब कई अन्य राज्यों के अनुकरण के लिए एक मॉडल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय अर्थशास्त्र सर्वेक्षण और खुद मोदी जी ने कोविड–19 से निपटने में योगी जी के प्रयास की प्रशंसा की।

पीएम मोदी जी ने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो न केवल एक परिवार सशक्त होता है, बल्कि समाज और देश का भी विकास होता है। उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है। यह व्यापक भागीदारी और चयन महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है, चाहे वह एंटी रोमियो स्क्वॉड के माध्यम से हो या प्रत्येक पुलिस स्टेशन में गुलाबी बूथों की स्थापना या मिशन शक्ति अभियान, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थय एवं आत्मनिर्भरता, गरिमा की परिकल्पना की गई हो। महिला एस.एच.जी ने कोविड –19 अवधि के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सामाजिक उद्यमिता मंच जैसे सामाजिक सहेली, महिला स्वयं समूहों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसने उन्हें बेहतर सोशल मीडिया सामग्री और प्रबंधन के माध्यम से व्यापक कस्टम आधार बनाने में मदद की है। लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन के सहयोग से महिलाएं अब केले के तनों को रेशे में बदल रही हैं। वे अब रोजाना 400–600 रुपये कमा रहे हैं। प्रेरणा ओजस पहल के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूहों को बच्चों के लिए सोलर लैंप बनाने में सक्षम बनाया गया है। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर रही है।

"विभा ग्राम सभा लोलाई, जनपद लखनऊ की रहने वाली हैं। वह लीड इंडिया नाम के एक स्वयं सहायता समूह के लिए काम करती हैं। लॉकडाउन के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी जी के शब्दों से प्रभावित और प्रेरित होकर, कि गांवों को मास्क बनाने के लिए कच्चा माल मुफ्त में मिलेगा और बदले में सब्सिडी मिलेगी, उन्होंने 12 महिलाओं को 'आत्मनिर्भर' बनने के लिए मास्क बनाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया।" ऐसे ही हजारों–लाखों किस्से हैं जो मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में नए आत्मानिर्भर उत्तर प्रदेश के किस्से रच रहें है।

मोदी जी और योगी जी के महिला सशक्तिकरण की मंशा के कारण ही महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण की उपलब्धता में सुधार हुआ है। बहराइच में महिला स्वयं सहायता समूह सहकारी खेती के माध्यम से साझा धन का निर्माण कर रहे हैं। यूपी सरकार ने अगले दो वर्षों में लगभग 2000 किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। महिलाओं को एफपीओ बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

लखनऊ के बाहरी इलाके कबीरपुर गांव की नवनिर्वाचित प्रथम महिला ग्राम प्रधान रीता वर्मा ने रिकॉर्ड समय में अपने गांव को कोविड मुक्त कराने के लिए दिन–रात प्रयास किया। वह अब अपने इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का लक्ष्य बना रही है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में, प्रमुख पदों पर जीतने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह योगी सरकार के महिला सशक्तिकरण अभियान में एक और मील का पत्थर है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लगभग 58,000 सदस्यों की देखभाल के लिए 50,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए एक परियोजना भी शुरू की। यह उन्हें 6000 रुपये की मासिक आय सहायता भी प्रदान करेगा। इस तरह महिलाएं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत में योगदान देंगी। मोदी जी ने यूपी में 58,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को 476 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए है।

महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की प्राप्ति में आर्थिक और सामाजिक रूप से योगदान दे रही हैं बल्कि कानून व्यवस्था लागू करने में अहम भूमिका भी निभा रही हैं। महिला एवं पुलिस बीट कार्यक्रम नामक पहल के माध्यम से 1537 थानों में महिला पुलिस कर्मियों को बीट पुलिस अधिकारियों के रूप में पोस्टिंग दी जाएगी।

महिलाओं,अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति और विकलांगों जैसे कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण से नीति प्रक्रिया में अधिक नागरिक भागीदारी के द्वार खुलते हैं और इस तरह पूरे समाज की भलाई में वृद्धि होती है। यह विकास की जरूरतों और मांगों में भी विविधता लाएगा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वास्तविकता तो यह है कि अब उत्तर प्रदेश महिलाओं के सशक्तिकरण को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पैमाने के रूप में देख रहा है योगी जी के तमाम भाषण हम देखें तो वह महिला हित के लिए समर्पित है आज चुस्त–दुरुस्त कानून व्यवस्था अपराधियों के प्रति योगी जी के सख्त तेवरों के चलते आधी रात में भी महिलाएं बेखौफ अपने घर जा सकती हैं और यह बहुत बड़ी बात है।

अंत में मैं आप सभी को मिशेल ओबामा के शब्दों के माध्यम से याद दिलाना चाहूंगी, 'महिलाओं के रूप में हम क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है'

और जिस तरह से मोदी जी और जोगी जी काम कर रहे हैं उसे देखते हुए यह कह पाना मुश्किल है की आत्मनिर्भरता एवं महिला विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अभी कितना और आगे जाएगा।

ISSN No. 2581-3528

डॉ. प्रदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
सत्यवती कॉलेज सांध्य, दिल्ली विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश की पहल जनसंख्या नियंत्रण कानून

जनसंख्या नीति से तात्पर्य ऐसी सरकारी घोषणा से है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि की जाए अथवा जनसंख्या नियंत्रण किये जाने से है किंतु आर्थिक विश्लेषण में जनसंख्या नीति से तात्पर्य किसी देश की उस जनसंख्या से है जिसमें उसका आकार एवं संरचना निश्चित की जाती है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 23.40 करोड़ के लगभग है जो की पूरे देश की संख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि बढ़ती आबादी की वजह से बहुत सी समस्याएँ भी आगे चल कर बढ़ेंगी। ऐसे में सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नीति के साथ इसे रोकने के लिए यह कदम उठा रही है। जनसंख्या की रोकथाम जरुरी है। समय समय पर सरकार इस दिशा में कई योजनाएं व कानून का गठन करती आई है। ऐसे में लोगों को जरूरत है कि वे इन कानूनों का पालन करें। हमारे देश में उत्तर प्रदेश की गणना सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में होती है। उ.प्र. जनसंख्या कानून ड्राफ्ट में मुख्यतः जनसंख्या को रोकने के बारे में जानकारी एवं उससे जुड़े नए कानून की जानकारी दी गई है। ऐसा ही एक नियम है, जिसमें जिन परिवारों के दो बच्चे या उससे कम बच्चे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार से कुछ सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। वही दो से अधिक बच्चे वाले परिवारों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित रखा जायेगा। अधिक बच्चे होने पर आप सरकार द्वारा दी गई बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ हो जायेंगे। सरकार ने यह घोषणा विश्व जनसंख्या दिवस पर की है, ताकि लोग इसके महत्व को समझें। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे उन्हें भी इस नीति के तहत प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह एक सराहनीय विचार है। वहीं इसमें एक कानून और जोड़ा जायेगा, जिसके अंतर्गत जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों में आवेदन करने से भी रोका जायेगा। नियम अनुसार उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी। यह नियम कड़े करने से ही लोग यह समझ पाएगें की जनसंख्या को रोकना कितना जरूरी है।

देश में लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से की जाती रही है। इस संबंध में पहली जनसंख्या नीति 1948 में आई इसके बाद इसमें 1974

तथा 1976 में कुछ बदलाव किए गए । इस नीति के विपरीत तीव्र जनसंख्या वृद्धि जारी रही प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जनसंख्या नीति 2000 लाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या की स्थिति हासिल करना था जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास हो और सब के लिए समान रूप से स्वच्छ वातावरण प्राप्त हो सके। आज जो स्थिति है उससे तो हम 2060 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए फिर भी देश की जनसंख्या 2010 में 1107 मिलियन होनी चाहिए थी जबकि 2008 में ही हमारे देश की जनसंख्या इससे भी ज्यादा 1149.3मिलियन हो गई।

2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस तरह की मांग में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। **15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक संकट पैदा करेगा।** लेकिन ये भी मानना होगा कि देश का एक जागरूक वर्ग इससे होने वाली समस्याओं को समझते हुए अपने परिवार को सीमित रखता है। ये लोग एक तरह से देशभक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं। जबकि अभी भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो इसके प्रभाव को नकारते हैं। **बीते साल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति निर्धारण की सलाह दी थी।** भाजपा के कई नेता गाहे–बगाहे इस मामले को उठाते रहते हैं। वहीं, हाल ही में असम में लागू होने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नजर डालें, तो इसमें साफ किया गया है कि राज्य के चाय के बागानों में काम करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े लोगों पर यह नीति और नियम लागू नहीं होंगे. भारत में धर्म और जाति की राजनीति अपने चरम पर है, अगर कोई नियम बनाया जाता है, तो संविधान के हिसाब से वह सभी लोगों पर लागू होना चाहिए लेकिन सरकारें अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को साधने के लिए इन नियमों में कुछ खास लोगों को छूट देती हैं। मिजोरम के एक मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चों वाले परिवार को एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मिजोरम में जनसंख्या घनत्व काफी कम है।

देश में लोगों के बीच ये आम धारणा बन चुकी है कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। भारत में गरीब और अशिक्षित तबकों से आने वाले ज्यादातर परिवारों में बच्चों की संख्या का अनुपात किसी शहरी या शिक्षित परिवार की तुलना में ज्यादा ही रहता है। गांवों में रहने वाले परिवारों में बच्चों की संख्या दो से ज्यादा होना आम बात है। हालांकि, कुछ सालों में इसमें भी कमी दर्ज की गई है और यह साक्षरता व जागरुकता आने की वजह से हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, 2001 में हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर 19.92 फीसदी थी, जो 2011 में घटकर 16.76 फीसदी पर आ गई। इसी तरह 2001 में मुस्लिम जनसंख्या में जो वृद्धि दर 29.5 फीसदी थी, वो 2011 में गिरकर 24.6 फीसदी हो गई। मुस्लिमों में जनसंख्या की वृद्धि दर हिंदुओं की तुलना में करीब 8 फीसदी ज्यादा है।

देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या एक अरब 22 करोड हो गई है। हमारी आबादी की वृद्धि दर 18000000 वार्षिक है चिंता की बात यह है कि विश्व की कुल आबादी का 16 प्रतिशत भारतीय है जबकि उनके पास विश्व भूभाग की मात्र 2 पॉइंट 4 प्रतिशत भू संपदा है। चीन की स्थिति इस मामले में हमसे काफी अच्छी है बढ़ती आबादी की ओर सरकार की चिंताएं तो हैं परंतु सरकारी प्रयासों के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि की गति जारी है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए हर वर्ष तरह–तरह के वायदे किए गए अनेक घोषणाएं की गई लेकिन जनसंख्या स्थिर नहीं हो रही है। सन 2000 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित करके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया था जनसंख्या नियंत्रण पर अब तक अरबों रुपया खर्च हो चुका है लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। देश में गरीबी, अशिक्षा और जातीय राजनीति की वजह से केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से ही कोई फायदा नहीं होगा अपितु जनता को इसके प्रति जागरुक और शिक्षित बनाना होगा। भारत के लगभग हर परिवार में लोगों की संतान के तौर पर पहली पसंद लड़का होता है। इस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कानून से लड़कियों को गर्भ में ही मारने की घटनाएं बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से पहले सरकार को इसके दुष्प्रभावों को लेकर लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून से जनसांख्यिकीय विकार पैदा होने का खतरा बढ़ने की सम्भावना रहती है।

देश की वर्तमान जनसंख्या 1.22 बिलियन है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या 1.35 विलियम चीन की है और भारत दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का 17 पॉइंट 31 प्रतिशत है यानी विश्व में हर छठा आदमी भारतीय है। जिस तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उम्मीद है कि 2030 तक भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में पहले नंबर पर आ खड़ा होगा। देश की वार्षिक वृद्धि दर 1.58 प्रतिशत के साथ 2030 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.53 विलियन होगी हर साल भारत में विश्व के दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है जो कि हम सभी के लिए चिंता का विषय है।

ISSN No. 2581-3528

उत्तर प्रदेश में राम गमन पथ और आर्थिक विकास की संभावनाएं

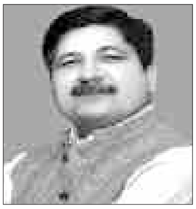

प्रोफेसर डॉ. हरेन्द्र सिंह
शिक्षाविद, शैक्षिक प्रशासक एवं चिन्तक

भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में श्रीराम अत्यन्त पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष हैं, इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। विश्व के कई देशों में श्रीराम आदर्श के रूप में पूजे भी जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता–पिता, यहां तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार, आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम के पिता राजा दशरथ ने श्रीराम की सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं दो इच्छाओं को पूरा करने का वर अर्थात वचन दिया था, कैकेयी ने दासी मन्थरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राजसिंहासन और राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी–खुशी चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। वनवास को जाते समय प्रभु श्री राम अयोध्या से निकलकर जिस–जिस मार्ग से गये उसी को राम गमन पथ कहा जाता है।

प्रभु श्रीराम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किमी की दूरी पर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज (इलाहाबाद) से 20–22 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषादराज गुह अथवा गुह्य का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। सिंगरौर में गंगा पार कर श्रीराम कुरई में रुके थे।कुरई से आगे चलकर श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयाग (इलाहाबाद) पहुंचे। प्रभु श्रीराम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट से निकलकर श्रीराम घने वन में पहुंच गए। असल में यहीं था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकाराण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। दरअसल, उड़ीसा की महानदी के इस पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्रप्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता–रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्रीराम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनियाभर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दण्डकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्रीराम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, राम–लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किमी दूर ताकेड गांव में 'सर्वतीर्थ' नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नामक स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया, क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने यहां जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध–तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। यहां से प्रभु श्रीराम आंध्रप्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित पर्णशाला पहुंचे जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहां पर राम–सीता का प्राचीन मंदिर है। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्रीराम–लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। इसके पश्चात् वे मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़े। यहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्रीराम ने वानर सेना का गठन किया और श्रीलंका की ओर चल पड़े। कोडीकरई समुद्र तट पर श्रीराम की सेना ने पड़ाव डाला और श्रीराम ने अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। श्रीलंका जाने के लिए पुल हेतु उपयुक्त स्थान न पाकर प्रभु श्रीराम जी की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया, जोकि एक शांत समुद्र तट है। यहां पर तीन दिन की खोजबीन के बाद श्रीराम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान धनुषकोडी ढूंढ़ निकाला, जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहां से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल अर्थात रामसेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है।

राम वनगमन मार्ग जोकि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रारंभ होगा, इस मार्ग के बीच कई जगहों पर प्रभु श्रीराम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ विश्राम किया था। प्रस्तावित 210 किलोमीटर का राम वन गमन मार्ग उत्तर प्रदेश में अयोध्या से चित्रकूट तक होगा। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग–28, राष्ट्रीय राजमार्ग–96 और राष्ट्रीय राजमार्ग 731 एक से गुजरेगा। राम वनगमन मार्ग में रामयणकालीन वृक्षों का रोपण किया जायेगा इनमें अशोक, साल, आम, परिजात कल्पवृक्ष, बरगद, चंदन, देवदारू, चंपा, नागकेसर, पुंनाग, महुआ, कटहल, असन, लोध, कदंब, अर्जुन, अक छितवन, अतिमुक्तक, मंदार, प्रियंगु, केश बकुल,

जामुन, अनार, कचनार, बेल, खैर, पलाश, बहेड़ा, पीपल, इंगुदी, शीशम, करीर, करौंदा, बज्जुल बेंत, तिलक, ताड़, तमाल, आंवला, मालती या चमेली, कुश, गे, सरकंडा, नीम, मल्लिका या बेला, सुपारी, बांस, चिरौंजी, धवक उर्फ़ बाकली, अंकोल, तेंदू, रीठा, वरण, तिनिश, बेर, धामन, भोजपत्र, कचनार, भिलावा, खस, सलई, नीवार, चिलबिल, केवडा, बड़हल, गर्जन, शमी, पाटल, कुंद, कनेर, करज्ज, बिजौरा, लिसोडा, कतक, सिदुवार, कुरंट, सेमल, मुचकुंद, सिरस, हिताल, सर्ज, चीड़, अमलतास, कुटज, बंधु जीव, पद्मक, रंजक व खजूर, रक्तचंदन, अगर, नारियल आदि प्रमुख रूप से होंगे। इसके अलावा इसमें श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी पर पुल के साथ नया रास्ता होगा। इस मार्ग का 38 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में होगा। वनगमन मार्ग अयोध्या से शुरू होकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर धाम, मंझनपुर, राजापुर होते हुए चित्रकूट तक जाएगा और चित्रकूट धाम को राम नगरी से जोड़ेगा। यह सभी धार्मिक स्थान आस्था और संस्कृति के बड़े केंद्र के रूप में बनकर उभर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण के बाद इनका महत्व भी काफी बढ़ जाएगा। इस मार्ग पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 44 स्थलों का चयन किया गया है। राम वनगमन मार्ग बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से विकास के कार्य होंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। चूंकि विकास का रास्ता सड़कों से ही होकर जाता है। इसलिए 132 किलोमीटर लम्बी सड़क को चार पैकजों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम पैकेज में मोहनगंज से औतारपुर की लम्बाई 35 किमी है। दूसरे पैकेज में औतारपुर से मूरतगंज की लम्बाई 29.682 किमी, जिसमें श्रृंगवेरपुर धाम पर गंगा नदी पर 6 लेन 1200 मीटर लम्बा पुल प्रस्तावित है। पैकेज तृतीय में मूरतगंज से महेवाघाट की कुल लम्बाई 48.068 है, इसे चार लेन चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इसमें मंझनपुर बाईपास एवं राजापुर बाईपास सम्मिलित है। पैकेज चतुर्थ में राजापुर से रायपुरा कुल लम्बाई 19.25 किमी है। इस प्रकार मोहनगंज से प्रारम्भ होकर चित्रकूट के निकट रायपुरा तक चारों पैकेजेज की कुल लम्बाई 132 किमी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3300 करोड़ होगी। इस मार्ग के निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से आने वाले तीन वर्षों में पूर्ण किया जायेगा। मार्ग निर्माण के साथ ही उन इलाकों का विकास को भी इससे जोड़ा जाएगा। इससे इन इलाकों का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के साथ ही आर्थिक लिहाज से भी तस्वीर बदलेगी। यह वनगमन मार्ग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है। इन रास्तों पर निर्माण कार्य करके इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्रीराम 14 साल के अपने वनवास के दौरान जिन रास्तों से गुजरे थे, वही मार्ग राम वनगमन पथ है। राम वनगमन मार्ग को रामायण कालीन वृक्षों से सजाया जाएगा और पूरा रास्ता बेला और चमेली से महकेगा। जगह जगह लगने वाले कदम, रसाल, अशोक, पारिजात, और जामुन आदि के वन त्रेतायुग के परिवेश को पूरी तरह जीवंत करेंगे। इनके पौधों का रोपण भी वैदिक रीति से होगा। महर्षि बाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में अयोध्या और इस मार्ग पर 88 प्रजातियों के वृक्षों का वर्णन मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना राम वनगमन मार्ग और उसके अगल–बगल पड़ने वाले ग्राम सभाओं में इसी प्रजाति के वृक्ष और वन लगाने की है।इसमें वृक्षों के अलावा झाड़ियां और घास भी शामिल हैं। इस वर्ष कुल मिलाकर 27,720 पौधों के रोपण किया जाना है।

इस मार्ग पर जहां –जहां वनगमन के दौरान भगवान श्रीराम ठहरे थे, राम वन के रूप में उन स्थलों को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे आठ वन क्षेत्रों को 137.45 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। अयोध्या से चित्रकूट के बीच आठ स्थानों पर राम वन बनाने की योजना भी तैयार की गई है। राम वनगमन के पथ के दोनों ओर हरित पट्टी भी होगी । अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट में राम वन बनाया जाएगा, लेकिन चित्रकूट का राम वन अयोध्या और प्रयागराज से विशेष होगा। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के साढ़े 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। प्रभु श्रीराम को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। शायद इसीलिए चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लाखों श्रद्धालु भगवान श्रीराम से जुड़े जन्म स्थलों को देखने के लिए चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट जिले के देवांगना हवाई पट्टी के पास रामायण काल के पौधों से राम वन तैयार किया जाना है। चित्रकूट के देवांगना हवाई पट्टी के समीप 35 एकड़ भूमि में बनने वाले इस रामायण कालीन राम वन की दूरी शहर से मात्र 6 किलोमीटर है। इस रामवन में 15 प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसमें चंदन, अशोक, बरगद, आम, पलाश, चमेली, धामन, कुंद, रीठा समेत तमाम पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। लगभग साढ़े 38 हजार पौधे इस राम वन में लगाए जाएंगे। इसके अलावा इस रामायण कालीन राम वन में औषधि वाटिका भी बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पौधों की सुरक्षा के लिए ब्रिक्स गार्ड भी लगाए जाएंगे। इन वनों के विकास से जहाँ एक ओर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर रोजगार के नये अवसरों का भी सृजन होगा, जिस से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को पंख लगेंगे। सड़कों के विकास के बाद क्षेत्र का रणनीतिक और आर्थिक विकास भी तेज़ी से होगा तथा लोगों को ज्यादा रोजगार और आमदनी भी प्राप्त होगी। राम वन गमन मार्ग के निर्माण के बाद श्रृंगवेरपुर धाम में धार्मिक पर्यटन का महत्व काफी बढ़ जाएगा। चित्रकूट और अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी तो होगी ही, श्रृंगवेरपुर धाम में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। कुंभ में भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इस मार्ग के निर्माण के बाद रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। पर्यटकों की संख्या बढने की वजह से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही इस मार्ग से कुछ दूरी तक दुकानें भी खोली जाएंगी, जिसमें होटल, ढाबे समेत तमाम ऐसी दुकानें रहेंगी, जिससे लोगों को फायदा होगा।

राम वनगमन मार्ग पर तीर्थों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को त्रेता युग का एहसास इस पथ पर होगा और आध्यात्मिक भावों को प्रतिबिंबित करते हुए इस पथ की अप्रतिम छटा को निहारने के लिए पर्यटक बार–बार उस पथ पर आने के लिए आकर्षित होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अयोध्या से चित्रकूट तक राम वनगमन मार्ग की सभी जगहों को सड़क मार्ग से जोड़ने की यह योजना भविष्य की अनेकों संभावनाओं के लिए नवीन मार्ग तो प्रशस्त करेगी ही, साथ ही साथ आने वाले सभी भक्तों को राम मंदिर के साथ–साथ वनगमन के पूरे पथ को देखने और समझने का अवसर भी प्रदान करेगी। जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जहां एक ओर बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लाखों की संख्या में रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे। राम वनगमन के पथ से आवागमन सुलभ व सुरक्षित होगा जिसके कारण बाहर के लोग यहां पर निवेश कर सकेंगे, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन उद्योग विकसित होगा और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश वासियों को उनके घर में ही रोजगार मिलेगा जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास पर पड़ेगा और अर्थ व्यवस्था में उत्तरोत्तर प्रगति एवं विकास की असीम संभावनाएं बनेंगी।

ISSN No. 2581-3528

एक जिला-एक उत्पाद

अनुपमा अग्रवाल
पत्र लेखिका एवं समाज सेविका

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जनपदों के मुख्य परम्परागत उत्पादों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक, प्रोत्साहन देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना लागू की है। जिसने उत्तर प्रदेश को न केवल विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाई है बल्कि उद्योग जगत को नई बुलन्दियों पर ले जाने का भी कार्य किया है जिस कारण आज दुनियाभर की अनेकों विदेशी कम्पनियां उत्तर प्रदेश का रुख कर रही हैं।कन्नौज का इत्र, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, बनारस का रेशम, आगरा का पेठा और चमड़ा, सहारनपुर का हस्तशिल्प, हाथरस की हींग, भदोही का कालीन, लखनऊ का चिकिनकारी व अलीगढ़ का ताला उद्योग आदि अनेकों उद्योग हैं जो मंदी की मार व गुणवत्ता में कमी के चलते अपनी पहचान लगभग खो से चुके थे, परन्तु 'एक जनपद–एक उत्पाद' योजना ने न केवल उद्योगों को गति प्रदान की बल्कि सरकारी वित्तीय सहायता ने इन उद्योगों से जुड़े लघु एवं कुटीर उद्योगों को एक बार पुनः जीवन दान देने का कार्य किया है।

'ओ डी ओ पी ने दिलाई उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान'

'वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट' के अंतर्गत अलीगढ़ के ताला एवं हार्डवेयर उद्योग को चुना गया है। इस योजना के लागू होने से मंदी की मार झेल रहे ताला उद्योग को उबरने का मौका तो मिला ही है साथ ही इस क्षेत्र में उत्पादकों के समक्ष आने वाली समस्याओं से जल्द छुटकारा मिलेगा ऐसी सम्भावना है। अलीगढ़ में तालों का इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर ब्रिटिश काल से ही तालों के लिए प्रसिद्ध है। 1842 से 1872 के मध्य डाक व्यवस्था के अंतर्गत डाक पत्र पेटिका में सुरक्षा की दृष्टि से ताले की आवश्यकता महसूस हुई। सर्वप्रथम ब्रिटिश उद्योगपति जे एच. जॉनसन द्वारा अलीगढ़ में ताले की फैक्ट्री स्थापित की गई इसके बन्द होने के पश्चात इसके मुख्य मिस्त्री हीरालाल ने 1887 में ताले का कारखाना खोला जहाँ सर्वप्रथम हैंड मेड ताला बनता था व बाद में डाई पंच तकनीक से लीवर लॉक और अब वर्तमान में पिन सिलेंडर तकनीक पर पैड लॉक, डोर लॉक, मल्टीस्टोल साइकिल लॉक, मल्टीपर्पज लॉक आदि आदि उच्च गुणवत्ता के ताले बनाये जा रहे हैं।

'तालों के शहर' के नाम से प्रसिद्ध अलीगढ़ व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ अपनी नमकीन, मिठाई, हार्डवेयर व शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। कच्चे माल व ऊर्जा की सहज उपलब्धता के कारण अलीगढ़ एक सफल व्यापार केंद्र के रूप में उभरा, कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता के पीतल, तांबा, लोहा व एल्युमीनियम, जिंक व स्टील धातुओं से निर्मित हार्डवेयर व तालों की अच्छी मांग होने के कारण यहां से पूरे देश दुनिया में उत्पाद निर्यात किये जाते हैं।यहां तालों की छोटी बड़ी 21780 पंजीकृत इकाइयां व इन पंजीकृत इकाइयों में 3010.77 करोड़ रु का इन्वेस्टमेंट है व 103366 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अतिरिक्त इनसे बहुत अधिक लगभग 50 से 60 हजार अपंजीकृत इकाइयां कार्यरत हैं जो शहर के हर गली मोहल्लों में अति सूक्ष्म, सूक्ष्म एवम लघु उद्योग के रूप में हैं जो लाखो लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। लाखों लोगों के घरों में चूल्हा जलाने वाले यहां के ताला उद्योग का पनपना भारत जैसे जनसंख्या प्रधान देश में उतना ही आवश्यक है जितना जीवित रहने के लिए जल एवम वायु का होना। इन सभी उद्योगों का वार्षिक टर्न ओवर लगभग 2000 करोड़ रुपये वार्षिक है।

लगभग 200 इकाइयों द्वारा अमेरिका, खाड़ी देशों, जर्मनी, फ्रांस, इग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात किये जाने वाले ताले व हार्डवेयर, आर्टवेयर, ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रिक गुड्स के कारखाने प्राचीन समय से ही शहर की घनी आबादी में कार्यरत है। ताला कारखानों से होने वाले जल एवं वायु प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह जी ने 1992 में रामघाट रोड पर ताला हार्डवेयर उद्योग के विकास के लिए ताला नगरी औद्योगिक संस्थान की स्थापना की परन्तु 27 साल बाद भी यह पूर्णतः विकसित नहीं है। यहां कुल 1100 प्लॉट हैं पर लालफीताशाही के चलते आधे ही प्लाटों पर फैक्ट्रियां संचालित हैं। उद्योगपतियों एवं निर्यातकों की मांग है कि केंद्र सरकार ताला नगरी को विकसित करने के लिए जरूरी कदम उठाए व नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें। यहां की अधिकांश फैक्ट्रियों में परम्परागत तरीके से उत्पादन होता है तथा एक ही स्थान पर ताले की रिताई, फिटिंग, चाबी की ढलाई, पॉलिश आदि कार्य न होने से उत्पादन लागत काफी बढ़ जाती है। जबकि आधुनिक मशीनों के आ जाने से यह लागत आधी रह जायेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

दुनिया भर के लोगों के घरों को सुरक्षा प्रदान करने वाला अलीगढ़ का ताला उद्योग आज सरकारी तन्त्र के असहयोग व चीन से टक्कर न ले पाने के कारण आज अपनी ही फैक्ट्री पर लटकने को मजबूर हो रहा है। आधुनिक तकनीक के अभाव एवं आर्थिक संकट के चलते आज कई सौ फैक्ट्रियां बन्द होने के कगार पर पहुंच गई थीं, जिससे उनमें कार्य करने वाले मजदूरों व उससे संबंधित सूक्ष्म इकाइयों पर भी रोजगार का संकट मंडराने लगा था।एक समय था जब अलीगढ़ में पूरे देश की जरूरत के करीब 75 फीसदी ताले बनते थे पर यह कारोबार अब अत्यंत विषम स्थिति में है, ताला कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में लगभग 1500 अति सूक्ष्म व सूक्ष्म कारखानों

ISSN No. 2581-3528

पर ताला लटक चुका है और 1000 से ज्यादा बन्द होने के कगार पर हैं। कभी लाखों लोगों को रोजगार देने वाले इस व्यवसाय में अब निरन्तर कमी आ रही है।

'प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "पिछली सरकारों की लापरवाही और उदासीनता के चलते अलीगढ़ का ताला एवं हार्डवेयर उद्योग बन्द होने लगे थे लेकिन हमारी सरकार में अलीगढ़ फिर से प्रदेश में चमकेगा तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हमने अलीगढ़ के ताला व हार्डवेयर उद्योग को इससे जोड़ा है ताकि यहां के लोगों को नई पहचान मिल सके"।

ओ.डी.ओ.पी. योजना के तहत उत्पादन किस तरह बढ़ाया जाए इसके लिए सरकार प्रशिक्षण देने की भी योजना बना रही है। साथ ही हर जिले में कॉमन फेसिलिटी सेंटर खोलने की सरकार की योजना है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर कारीगर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिले के चिन्हित उत्पादों के विकास के लिए सुविधाएं मुहैया कराना है ताकि, उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार आसानी से उपलब्ध हो सके। इसी के साथ छोटे उत्पादकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के साथ मार्जिन मनी में 25 फीसदी छूट देने की सरकार की योजना है ताकि वे लघु स्तर पर अपनी स्वयं की इकाई लगा सकें और आत्मनिर्भर बन अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करें। कारोबारियों का कहना है कि इस उद्योग से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी समस्या उधारी है, बिक्री के अनुसार भुगतान न मिलने से पूंजी का संकट खड़ा हो जाता है, मध्यम उद्योग तो इस संकट को झेल जाते हैं लेकिन छोटे कारखानों के मालिकों के सामने आर्थिक तंगी सामने आ जाती है और यही कारण है कि लगातार छोटे कारखाने बंद होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एमएसएमई में पंजीकृत न होने के कारण कच्चे माल पर भी छोटे कारोबारियों को सरकारी छूट का लाभ नहीं मिल पाता। एम एस एम ई में पंजीकरण हेतू वृहद अभियान की जरूरत है। उद्योग के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का ठीक न होना व अवैध परिवहन है। अवैध परिवहन पूरी तरह बन्द हुए बिना उद्योग की प्रगति व राजस्व में बढोत्तरी दूर का स्वप्न है अवैध परिवहन जी एस टी में पंजीकृत उधमियों के समक्ष बड़ा संकट है।जहां चीन एक सप्ताह के भीतर दुनिया के किसी भी देश में अपना माल पहुंचा देता है वहीं यहां के माल की डिलीवरी एक माह में पहुंच पाती है।

'वर्तमान समय में ताला एवम हार्डवेयर उद्योग की समस्याएं' –

1. विद्युत दरों में अप्रत्याशित वृद्धि।

2. UPSIDA में अराजक माहौल।

3. सिंगल विंडो सिस्टम पूरी तरह फेल।

4. प्रदूषण, श्रम, अग्निशमन, पीएफ, विद्युत आदि विभागों में अत्यधिक भ्रष्टाचार।

5. बैंकों द्वारा MSME क्षेत्र को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ब्याज दरों की छूट न दिया जाना व MSME को बिना सम्पत्ति बन्धक किये सरकार की क्रेडिट गारण्टी फण्ड में कवर करके ऋण न देना।

6. श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई नई प्रक्रिया अग्निशमन व पर्यावरण की सहमति आवश्यक करने से इस सीमा में न आने वाले सूक्ष्म उद्योग के समक्ष समस्या उत्पन्न हो सकती है।

7. स्थानीय निकाय द्वारा औद्योगिक संपत्ति कर / हाउस टैक्स में 8 से 10 गुना वृद्धि ग्रह कर से 3 गुना करना भी उद्योग जगत के समक्ष गहरा संकट खड़ा करेगा ।

समस्या निवारण हेतु सुझाव :–

1. औद्योगिक भूखंड उचित दरों पर उपलब्ध कराए जाएं तथा नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायें व औद्योगिक सर्किल रेट कम किये जायें।

2. MSME के लिए भूखंड की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी कम की जाय।

3. UPSIDC vc UPSIDA में लीज डील पूर्व की भांति सौ रुपये के स्टाम्प पर ही हो न कि सर्कल रेट पर रजिस्ट्री की दरें चार्ज हों।

4. औद्योगिक क्षेत्र की बाउंड्री कराई जाए यह विषय UPSIDC के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में है।

5. यूपीसीडा द्वारा आवंटित प्लॉटों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर फ्री होल्ड किया जाए।

6. अलीगढ़ के उधोग में इकाइयों द्वारा घर घर में उत्पादन होता है, भू उपयोग के नाम पर उद्योग बन्द करने की साजिश रची गयी है जबकि सरकार द्वारा अपेक्षित औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित नहीं किये गए व अति सूक्ष्म व सूक्ष्म उद्योग की आर्थिक स्थिति जमीन क्रय कर निर्माण करने लायक नहीं है अतः पारम्परिक औद्योगिक मोहल्लों को 'मिश्रित आबादी' क्षेत्र घोषित करना हितकर होगा।

7. प्रदूषण उद्योग की स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस प्रकार हम श्वांस लेकर co2 निकालते है व भोजन ग्रहण कर मल का त्याग करते हैं उसी प्रकार लघु उद्योग से स्वाभाविक हल्का फुल्का प्रदूषण हो सकता है पर आवश्यकता है प्रदूषण के नाम पर उद्योग की बन्दी व बर्बादी की जगह प्रदूषण नियंत्रण व उसके उपकरण लगाने पर ध्यान दिया जाए व आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाये।

8. प्लेटिंग की इकाइयों से निकलने वाले जल के निस्तारण हेतु सामूहिक ETP प्लान्ट लगाने की आवश्यकता है यह प्रयोग गत 15 वर्षो से लुधियाना पंजाब में सफलता पूर्वक चल रहा है हर इकाई से दूषित जल टैंकर द्वारा एकत्रित कर एक ही जगह शोधित होता है लघु उद्योग इस प्लांट का व्यय व्यक्तिगत वहन नही कर पाते।

9. विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत ज्यादा विकास शुल्क लिए जाने के बाद भी कोई विकास का कार्य नहीं किया जाता MSME को इस विकास शुल्क से मुक्त किया जाना भी अति आवश्यक है।

ISSN No. 2581-3528

इथेनॉल (Ethanol) उद्योग एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश

डॉ. अखिलेश मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र)
एस. डी. पी. जी. कॉलेज, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ही नही अपितु विश्व के मात्र सात ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या इस राज्य से अधिक है। उतर प्रदेश राज्य की सांस्कृतिक विरासत न केवल अद्वितीय है बल्कि, इस राज्य ने सदैव देश की राजनीति एवं अर्थतंत्र को नई दिशा दी है। अपनी भागौलिक संरचना एवम सांस्कृतिक धरोहरों के कारण इस राज्य को सदियों से आक्रांताओं के आक्रमण एवम विभीषिका को झेलना पड़ा है उसके बावजूद यह राज्य न केवल अपने पैरों पर खड़ा हुआ बल्कि, देश की प्रगति एवम संवृद्धि में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान करता रहा है। जब राष्ट्र में खाद्यान्न संकट चरम पर था तो राज्य के किसानों ने हरित क्रांति को सफल बनाते हुए खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जबसे देश में गन्ना को वाणिज्यिक फसलों में शामिल किया गया तब से प्रदेश में खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई। इसके कारण से प्रदेश मे न केवल देश में चीनी एवं अन्य कृषि आधारित औद्योगिकरण का तेजी से विकास हुआ बल्कि, गन्ना उत्पादक किसानों की आय एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। हालांकि इस दौरान गुड, शक्कर एवं सीरा से जुड़े उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि नही हो पाया। इस कारण किसान की आत्मनिर्भता चीनी मिलों पर तेजी से बढ़ती गई।

1980 के दशक में भारत के चीनी उद्योग को ब्राजील, क्यूबा पाकिस्तान एवं अन्य देशों से चुनौती मिलना प्रारंभ हो गया। गन्ना की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी प्रतियोगी देशों की तुलना में कम होने के कारण तुलनात्मक लागत भी बढ़ा है। चीनी एवं एल्कोहल के सिंथेटिक एवं अन्य विकल्पों के विकास के कारण देश के चीनी उद्योग एवं गन्ना किसानों को घरेलू एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की इन्ही समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार कई विकल्पों पर शोध एवं विकास के लिए प्रयासरत थी जिसमें शीरे से एथेनाल के रूप में चमत्कारिक विकल्प मिल गया। एथेनाल बायो वेस्ट से बनने वाला एक ऐसा उत्पाद है जिसके अनेकों वाणिज्यिक उपयोग है।

इथेनॉल (Ethanol)– इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो शक्कर और चुकंदर के व्यर्थ से बचे पदार्थो के औद्योगिक प्रसंस्करण से बनाया जाता है। शीरे में लगभग 30 से 35 प्रतिशत तक गन्ने की शक्कर तथा इतना ही ग्लुकोस और फ्रुंक्टोस घुला रहता है। शोरे का आपेक्षिक घनत्व 1.03 से 1.04 लाने के लिए इसमें जल मिलाया जाता है। जीवाणुओं तथा अन्य अनावश्यक वैक्टीरिया की वृद्धि रोकने के लिए, इस घोल में सल्फ़्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। फिर इसमें थोड़ा सा यीस्ट डालकर इसे 30–40 सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। लगभग 40 से 50 घंटों में फर्मेंटेशन समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में शीरे की लगभग 95 प्रतिशत शक्कर विच्छिन्न होकर ऐल्कोहल और कार्बन–डाई–आक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस विधि से प्राप्त एल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य

क्रम	राज्य	क्षेत्र (मिलियन हे०)	भारत के सम्पूर्ण उत्पादन मे हिस्सा	कुल उत्पादन मिलियन टन मे	भारत के सम्पूर्ण उत्पादन मे हिस्सा (% मे)	उत्पादकता किलो/हे०
1	Andhra Pradesh	0.19	3.89	14.96	4.37	78.7
2	Assam	0.03	0.61	1.08	0.32	36.0
3	Bihar	0.25	5.12	12.76	3.73	51.0
4	Gujarat	0.19	3.89	13.76	4.02	72.4
5	Haryana	0.09	1.84	6.04	1.76	67.1
6	Karnataka	0.42	8.61	39.66	11.58	94.4
7	Madhy Pradesh	0.07	1.43	2.67	0.78	38.1
8	Maharashtra	0.97	19.88	81.9	23.92	84.4
9	Odisha	0.01	0.2	0.9	0.26	90.0
10	Punjab	0.07	1.43	4.17	1.22	59.6
11	Tamil	0.32	6.56	34.25	10	107.0
12	Uttar Pradesh	2.13	43.65	120.55	35.21	56.6
13	Uttarakhand	0.11	2.25	6.5	1.9	59.1
14	West Bengal	0.02	0.41	1.13	0.33	56.5
15	Others	0.01	0.2	2.05	0.6	-
16	All India	4.88	100	342.38	100	70.1

उपरोक्त टेबल से स्पष्ट है कि 2014 में देश में कुल बोये जाने वाले गन्ना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 43 प्रतिशत है जबकि, कुल चीनी मीलों में उत्तर प्रदेश (155) का क्रम महाराष्ट्र (195) के बाद आता है। नीतियों में अस्पष्टता, नीति नियंताओं की अदूरदर्शिता, लालफीताशाही, चीनी मिल मालिको, शराब माफिया, नौकरशाहों –राजनीतिज्ञों के अपवित्र गठजोड़ के कारण गन्ना विकास पर पर्याप्त

ISSN No. 2581-3528

ध्यान न देने के कारण गन्ना के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता एवं एथेनाल उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी संभावनाओं से काफी कम रही थी। किन्तु, सन 2017 में मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सत्ता सभालते ही नई ईंधन नीति के प्रावधानों को लागू करते हुए प्रदेश की एथेनाल नीति 2017–18 की घोषणा की। तब से लेकर अब तक प्रदेश एथेनाल उत्पादन में नित–नए रिकार्ड एवम प्रतिमान स्थापित कर रहा है।

एथेनॉल का उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होती है लेकिन शर्करा एवम स्टार्च सघन कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। एथेनाल एक बायो फ्यूल होने के कारण 35 फीसदी कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को तो कम करता ही है, इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35 फीसदी ऑक्सीजन होता है जिसके इस्तेमाल से वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है।

जुलाई 2021 में 54 डिस्टलियरी के माध्यम से 58 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है। केंद्र सरकार की नई ईंधन नीति के अनुसार देश में सन 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत तथा 2030 तक इसे 20 प्रतिशत ब्लेडिंग करने का लक्ष्य है। इस कारण देश में औद्योगिक एवं ईंधन इथेनॉल की बहुत बड़ी मांग होगी जिसके लिए बड़े स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाते लालफीताशाही को समाप्त करने एवं स्थानीय उद्यमिता के विकास हेतु, जुलाई 2021 में सिंगल विंडो क्लीयरेंस नीति की घोषणा की जिसके तहत आवेदन कर्ता को आवेदन करने के दिन से 15 दिनों के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। यदि विभाग बिना किसी ठोस कारण के लाइसेंस देने में टाल मटोल करता है तो आवेदनकर्ता का लाइसेंस स्वतः स्वीकृति मान लिया जाएगा।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुमान के अनुसार सन् 2030–31 में घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए 68.5 मिलियन टन पेट्रोल की मांग होगी तथा यदि 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग की अनुमति होगी तो इस हिसाब से देश में 13.8 मिलियन टन एथेनोल की आवश्यकता होगी। पेट्रोल के अलावा एथेनोल ब्लेंडिंग को डीजल में भी सरकार नें अनुमन्य कर दिया है। हरित ईंधन के एक महत्वपूर्ण विकल्प एवं किसानों की आय वृद्धि की संभावना को देखते हुए, पेट्रोलियम मंत्रालय ने अगले पांच साल के लिए इथेनॉल की खरीद करने की गारंटी देने को तैयार है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने तथा डीजल एवम पेट्रोल में इसके ब्लेंडिंग का सर्वाधिक लाभ यह होगा कि इससे जहां पेट्रोलियम पदार्थों के आयात का बोझ कम होगा वहीं इस प्रक्रिया एवम् इसकी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े लोगो की आय एवम रोजगार में वृद्धि हो सकेगी तथा प्रदेश में आत्मनिर्भरता आ सकेगी। चूँकि, इसमें बहुत अधिक तकनीकी विशेषज्ञता एवं पूंजी की ज्यादा आवश्यकता नही है अतः इसे उत्तर प्रदेश के किसान, किसानों के समूह, स्वयं सहायता समूह एवं एन जी ओ स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते है एवं प्रधानमन्त्री जी के हरित विकास की संकल्पना में अपना उत्तरोतर योगदान कर सकते हैं।

ISSN No. 2581-3528

मुजफ्फरनगर में गुड़ उद्योग सीमित संसाधन असीमित अवसर

चन्द्रभूषण सिंह
आई.ए.एस
जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर

जनपद मुजफ्फरनगर प्रदेश का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला है यह क्षेत्र गंगा–यमुना दोआब क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी से युक्त है। जनपद मुजफ्फरनगर एशिया महाद्वीप का एक मात्र ऐसा जनपद है जहां पर आठ चीनी मिल की वृहद इकाईयां स्थापित एवं संचालित हैं, इन वृहद इकाईयों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 8000 लोगों का रोजगार प्राप्त है। जिले के लगभग 2 लाख 15 हजार से अधिक कृषक गन्ना खेती में संलग्न हैं। गन्ना और गुड़ की मिठास ही जनपद मुजफ्फरनगर की प्रमुख पहचान है। साथ ही साथ अगर यह कहा जाए कि मुजफ्फरनगर की ख्याति गन्ना और गुड़ उत्पादन से है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुड़ का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रन्थ छांदोग्य उपनिषद, मत्स्यदण्डिका आदि में मिलता है।

गुड़ बनाने का कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे समय से चला आ रहा है। गुड़ बनाने का कार्य मुख्यतः खाण्डसारी इकाईयों तथा कोल्हुओं द्वारा किया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 1000 परम्परागत कोल्हू संचालित हो रहे हैं। जिनके द्वारा जनपद के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत उपभोग कर गुड़ बनाया जाता है। जनपद में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मण्डी स्थापित है, जो स्वयं में यह परिलक्षित करती है कि जनपद का गन्ना और गुड़ जनपद के विकास के रीढ़ की हड्डी है। इन्ही सब विशेषताओं के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर का चयन एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत गुड़ उत्पादन हेतु किया गया है। जनपद में गुड उत्पादकों द्वारा गुड़ में वैल्यू एडीशन का कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार के गुड़ जैसे – लड्डू, गुड़ की टाफी, बर्फी, चाकू एवं खुरपा आदि के रूप में बनाया जा रहा है। गुड़ की टाफी बच्चों की सेहत के लिए काफी लाभप्रद है, इससे उन्हें प्रचुर मात्रा में आयरन, मैग्निश्यिम, कैल्शियम व अन्य मिनरल्स मिलते है। गन्ना एवं गुड़ उत्पादकों के लिए ये उत्पाद उपयोगी हो रहे हैं, जिससे प्रदेश, देश और देश के बाहर भी इन उत्पादों की महत्ता बढ़ रही है। गुड़ एक सीमित संसाधन होते हुए असीमित अवसर पैदा कर रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, स्थानीय एवं परम्परागत उद्योगों को विस्तार देने हेतु एक जनपद एक उत्पाद योजना की घोषणा 24 जनवरी, 2018 को की गयी। यह योजना उद्योग विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। विगत तीन वित्तीय वर्षों (2018–19, 2019–20, 2020–21) में एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत कुल 32 इकाईयों को रू. 826.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराकर गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। अनुदानयुक्त ऋण के प्रोत्साहन से जनपद में आधुनिक तकनीक से गुड़ बनाने वाली इकाईयों की स्थापना हुई है। जैविक गन्ने से गुड़ बनाने वाले उत्पादकों का उत्साह बढ़ा है, क्योंकि इन उत्पादकों को एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश व प्रदेश के बाहर लगने वाले मेलों में अच्छा बाजार मिला है तथा उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलने से इनके उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

गुड़ उद्योग में लगे अकुशल कारीगरों को कुशल बनाने हेतु 'एक जनपद एक उत्पाद टूलकिट प्रशिक्षण योजना' संचालित है, जिसके द्वारा अकुशल कारीगरों को दस दिवसीय प्रशिक्षण दिलाकर विविध प्रकार के हाईजीनिक गुड़ बनाने की जानकारी दी जाती है। तथा उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराये जाते हैं।

एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत सामान्य केन्द्र (सी.एफ.सी) योजना संचालित है। जिसमें शासन द्वारा 90 प्रतिशत या अधिकतम रू. 12.75 करोड़ की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। जनपद मुजफ्फरनगर में सामान्य सुविधा केन्द्र योजना के अन्तर्गत तीन प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित होकर मुख्यालय/शासन को प्रेषित किये गये हैं। इसमें से एक प्रस्ताव मैसर्स – बधाई एग्री बिजनेस प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, बधाई कला मुजफ्फरनगर है, जिसकी प्रोजेक्ट राशि रू. 510.10 लाख है, जो मुख्यालय/शासन द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत हो गया है तथा दिनांक 23 जून 2021 को इसका ऑनलाइन शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा सामान्य सुविधा केन्द्र गठन के दो प्रस्ताव मैमर्स– जैविक किसान आर्गेनिक फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, शेरपुर पुरकाजी (प्रोजेक्ट धनराशि रू. 823.00 लाख) एवं मैमर्स– ग्रोमोद्योग जेगरी प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, जानसठ मुजफ्फरनगर (प्रोजेक्ट धनराशि रू. 978.00 लाख) मुख्यालय/शासन स्तर पर स्वीकृत (प्राथमिक स्तर पर) किया जा चुका है।

जनपद की कुछ महत्वपूर्ण गुड़ उत्पाद की इकाईयां जैसे– मै. राठी गुड़ उद्योग छछरोली, जिला मुजफ्फरनगर, मै. आकाश गुड़ मेरठ रोड मुजफ्फरनगर, मै. अर्पण गुड़ पैकेजिंग, औ. आ. मुजफ्फरनगर, मै. बेबो जेगरी ग्राम गडवाडा जिला मुजफ्फरनगर, मै. प्रदीप गुड़ उद्योग ग्राम जटमुझेडा जिला मुजफ्फरनगर, मै. अजय गुड़ उद्योग, ग्राम सदरूदीननगर जिला मुजफ्फरनगर, मै. इन्द्रजीत गुड़ उद्योग ग्राम नाईपुरा जिला मुजफ्फरनगर आदि हैं।

इस प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर में गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग निरन्तर विकास के नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के नये अवसर सृजित हो रहे है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, जिसके कारण वह चीनी की बजाय हाईजीनिक गुड़ को प्रयोग करने में रूचि ले रहा है। इसीलिए बाजार में गुड़ की मांग निरन्तर बढ़ रही है। फलस्वरूप एक जनपद एक उत्पाद योजना द्वारा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था के सपनों को साकार किया जा रहा है। यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जैसे–जैसे हमारा समाज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा वैसे ही गुड़ एवं खाण्ड के प्रति लोगों का रूझान बढ़ता जायेगा। भविष्य में जितना ही गुड़ का उत्पाद हाईजीनिक होगा उतना ही बड़ा बाजार हमारे पास उपलब्ध होगा।

ISSN No. 2581-3528

संकल्प से सिद्धि करता उत्तर प्रदेश

डॉ. उर्विजा शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर
एस. डी. पी. जी. कॉलेज, गाजियाबाद

कहा गय है कि यदि हम संकल्प लेकर कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होती है। गत वर्षों में उत्तर प्रदेश में हो रहा चहुंमुखी विकास अथवा कहे 'परिवर्तन' भी सतत् प्रयासों का परिणाम है। वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया उद्बोधन इन प्रयासों की कहानी स्वयं ही व्यक्त करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश एक प्रकार से धर्म, संस्कृति का केन्द्र बनने के साथ–साथ आर्थिक स्वावलम्बन की ओर बढ़ रहा है। "ईज ऑफ डूइंग बिजलो" में उत्तर प्रदेश द्वितीय पायदान पर है। यह उपलब्धि बहुत बड़ी है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि जब इस प्रदेश में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि करने से भयभीत होता था। उत्तर प्रदेश में भव्य फिल्म सिटी के निर्माण की घोषण होना भविष्य के लिए यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगी। यह कल्पनातीत ही था कि इतने वर्षों से मुंबई जो फिल्म नगरी बनी हुई थी उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश में फिल्म–निर्माण हेतु साधन उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं है जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण करने हेतु है। उदाहरण के लिए 'यूपी कन्या सुमंगला योजना', उत्तर प्रदेश किसान योजना, उत्तर प्रदेश रोजगार मेला, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, उत्तर प्रदेश जनसुनवाई, वृद्धाश्रम पेंशन योजना, मजदूर भत्ता योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल, सरकारी कर्मचारियों हेतु मानव–संपदा पोर्टल, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी आसान किस्त योजना, यूपी निवेश मित्र, पारदर्शी किसान सेवा योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन आदि। इसके अतिरिक्त उक्त योजनाओं से जुड़ी अनेक योजनाएं ऐसी है जो जनकल्याण की वाहक हैं। यह सरकार के संकल्प को दर्शाती है। कोरोना महामारी की प्रथम और द्वितीय लहर को अनगिनत प्रयासों से नियंत्रित करने का प्रयास भी वर्तमान सरकार की संकल्पसिद्धि को दर्शाता है। यद्यपि इस दौरान हजारों की संख्या में लोग इस महामारी से न केवल संक्रमित हुए वरन काल का ग्रास भी बने। तथापि 'मिनी भारत' कहलाये जाने वाले उत्तर प्रदेश ने जिस जिजीविषा एवं कर्मठता का परिचय दिया वह सराहनीय रहा। यदि देश के अन्य राज्यों में इसकी तुलना की जाये तो 'महामारी काल' में सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का अंतर साफ दिखाई देता है।

उत्तर प्रदेश भारत की 'लघु छवि' दिखाता है। इस कारण यह प्रदेश अनेक धर्मों जाजियों एवं समुदायों का केन्द्र भी है। प्रत्येक नागरिक हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना चुनौती है, किन्तु फिर भी यहां के नागरिकों का जीवन–स्तर सुधरा है, यद्यपि अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है।

विगत 500 वर्षों से सनातम धर्म एवं संस्कृति के संघर्ष के प्रतीक के रूप में अयोध्या में हो रहे 'भव्य राम मंदिर का निर्माण' प्रसन्नता के साथ–साथ गौरवशाली क्षण है। इस मंदिर के निर्माण के साथ–साथ एक विशाल कॉरिडोर का निर्माण करना यह सिद्ध करता है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में पर्यटन के भी अवसर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, गोरखपुर, गाजियाबाद आदि भविष्य में उत्तर प्रदेश का विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस नगरों के साथ–साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी समृद्ध करेंगे। वर्तमान समय में सम्पूर्ण देश में केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जो धर्म, संस्कृति व आस्था का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। साथ ही 'स्मार्ट सिटी' की प्रतिस्पर्धा में भी प्रदेश के अनेक नगर सम्मिलित हैं। जेवर में बनने वाला 'अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' विश्व का विशालतम सुविधाओं से भी युक्त होगा। यह सब निरंतर किये गये कृत्यों का फल है। किन्तु कुछ ऐसे प्रश्न व समस्याऐं भी जिनका समाधान आवश्यक है। इसमें सबसे गंभीर विषय धर्मांतरण है। धार्मिक उन्माद, जातीय विद्वेष, भाई भतीजावाद, क्षेत्रीय विषमताएं, लिंगभेद, लव–जिहाद, बेरोजगारी ऐसे जटिल प्रश्न है जिनका उत्तर शीघ्र ही तलाशना होगा। राजनीतिक छल–प्रपंचों के कारण आज भी न जाने कितनी राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। सांप्रदायिकता एक ऐसा विषैला सर्प है जो सारे समाज में विषवमन कर रहा है। समस्याओं से त्राण पाने का यही सही समय है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। यद्यपि प्रत्येक जनपद से '75 शिक्षक सम्मान प्रदान कर वर्तमान सरकार सकारात्मक प्रयास कर रही है। तथापि बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं को संकीर्ण मानसिकता से निकालकर एक संपूर्ण एवं संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित करें। यह तभी संभव है जब हम न केवल सरकार के प्रयासों की पूर्ति में सहयोग करें वरन् स्वयं भी अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करें। दूसरों पर दोषारोपण एवं छिद्रान्वेषण करने से श्रेष्ठ है कि स्वयं आत्ममंथन कर आत्मसुधार करें। तभी हमारे संकल्पों से न केवल प्रदेश वरन् देश भी सिद्धि प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं को संकीर्ण मानसिकता से निकाल एक संपूर्ण एवं संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित करें। यह तभी संभव है जब हम न केवल सरकार के प्रयासों की पूर्ति में सहयोग करें वरन् स्वयं भी अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करें। दूसरों पर दोषारोपण एवं छिद्रान्वेषण करने से श्रेष्ठ है कि स्वयं आत्ममंथन कर आत्मसुधर करें। तभी हमारे संकल्पों से न केवल प्रदेश वरन् देश भी सिद्धि प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेगा।

ISSN No. 2581-3528

सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के पटल पर अयोध्या

डॉ. प्रियंका सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
शम्भू दयाल पीजी कॉलेज, गाजियाबाद

सांस्कृतिक नगरी अयोध्या का नाम सुनते ही प्राचीन भारत के इतिहास का गौरवशाली रामायण काल सहर्ष याद आ जाता है। क्योंकि वह काल न केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता को स्थापित करने वाला काल था अपितु पवित्र वेदों, शास्त्रों व साहित्य की रचना का काल था। रामराज की परिकल्पना को समाज में पुनर्स्थापित करके सत्य की संकल्पना को विराजमान करने की आवश्यकता है। रामराज से पोषित अयोध्या नगरी अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रख्यात है। वह भगवान राम को अपने हृदय में लेकर असीम श्रद्धा के भवसागर में आज भी गोते खा रहा है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अयोध्या वर्तमान में सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का केन्द्र भी बन रहा है। सांस्कृतिक अर्थशास्त्र से तात्पर्य अर्थशास्त्र के उन उपखंडों से है जो संस्कृति और आर्थिक मूल्यों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। जिसमें ज्ञान परक मूल्यों का समावेश होता है। सांस्कृतिक अर्थशास्त्र से अभिप्राय आर्थिक गतिविधि का वह भाग जो सांस्कृतिक उत्पादों व गतिविधियों से संबंधित है। अन्य शब्दों में, एक ऐसा आयाम जो सांस्कृतिक संचार के साथ आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न करें। निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घोषणा और उसकी आधारशिला ना केवल भारत के इतिहास में आध्यात्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों को पोषित करता है अपितु पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर अयोध्या की आर्थिक स्थिति का भी पुनरुद्धार करता है। साथ ही अयोध्या से जुड़े अन्य सांस्कृतिक व आध्यात्मिक स्थलों से भावात्मक संबंध स्थापित करता है। इन माध्यमों से अयोध्या अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित कर विश्व में अपनी विरासत की छठा बिखेर रहा है। ज्ञातव्य है जब कभी कोई स्थान या शहर सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तो वह अन्य कई आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है। उसका यह स्वभाव वहां के रहने वाले लोगों की जीवन शैली उनकी रहन–सहन को प्रतिष्ठित करने में योगदान करती है। साथ ही कई ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है जिसे रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं और वहां के लोग अपनी जमीन व माटी की खुशबू को आत्मसात करते हैं, एवं अपनी आर्थिक स्थिति की स्थिरता के साथ एक अलग आनंद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने हेतु पलायन करने को विवश लोग आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी अपनी जन्मभूमि की सांस्कृतिक विरासत का विश्व में प्रतिष्ठित होना उन्हें अभिभूत कर देता है। जिस प्रकार अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हुआ वह एक गौरवशाली क्षण है। अयोध्या नगरी की गरिमा के अनुरूप दीपोत्सव के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। अपने शासनकाल में योगी सरकार ने जिस प्रकार सुशासन स्थापित किया वह अपने आप में मिसाल है। ऐसे भव्य एवं दिव्य आयोजनों को सांस्कृतिक नगरी अयोध्या में करा कर योगी सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से उसे विश्व पटल पर स्थापित किया है और साथी ही एक साथ इतने दीपक जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार पांचवा दीपोत्सव मनाने जा रही है जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ता के संकेत मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है जहां उसकी उपयोगिता दूसरे पायदान पर होती है।

मंदिर पर्यटन के आंकड़ों पर ध्यान दें तो यह भारत में कई अरब डॉलर का उद्योग है और बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न करता है। राज्य में एक सघन मानव शक्ति होने के कारण आज इसकी महती आवश्यकता है। राम मंदिर निर्माण व राम गमन मार्ग का विस्तार उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनने की क्षमता रखता है। इसी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के दृष्टिगत 85 करोड़ रुपए आवंटित किए है जिससे बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। राम मंदिर निर्माण के साथ ही सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त अस्पताल और होटल के लिए भी प्रमुख परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं जिन पर सरकार के साथ–साथ निजी क्षेत्र भी कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2020–21 में अयोध्या में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 100 करोड रुपए आवंटित किए हैं। ज्ञातव्य है कि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ रियल स्टेट क्षेत्र में भी उछाल आना स्वाभाविक है। जिसका सबसे ज्यादा लाभ वहां के निवासियों को होगा। लोग अपनी भूमि से एक अच्छे किराए के अवसर को प्राप्त कर सकेंगे साथ ही उस स्थान से जुड़े कई स्थानों में भी इसका प्रभाव दिखेगा। निश्चित रूप से यह विकास मार्ग छोटा नहीं है और इस क्षेत्र की क्षमता को पूरी तरह साकार करने में तथा उसके सदुपयोग करने में कुछ वर्ष लग सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा प्रारंभिक बिंदु होगा। सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या धाम के लिए एक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही स्थान के विकास हेतु अयोध्या में अन्य पर्यटन सुविधाओं के विकास व सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है।

राम मंदिर की आधारशिला रखने से अयोध्या और उसके आसपास के स्थानों के आर्थिक पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है. जिसमें विकास के साथ श्रद्धा भाव भी समाहित है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है और श्रद्धेय भगवान राम की घर वापसी का प्रतीक है।

ISSN No. 2581-3528

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में युवाओं का योगदान

डॉ. राहुल त्यागी
स्वतंत्र लेखक

भारत में कोरोना की दूसरी लहर के क्षीण होते ही देश तेज़ी से पटरी पर लौट रहा है। वित्त वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही के आंकड़ों पर नज़र डालें तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नतीजे घना कोहरा छँटने जैसे प्रतीत होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी राजस्व संग्रह बीते अगस्त माह में 1.12 लाख करोड़ के उत्साह वर्धन आंकड़े को पार कर गया,जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 फ़ीसदी अधिक रहा है। मुश्किल समय में भी जीडीपी में इतना उछाल और बढ़ता जीएसटी राजस्व इशारा करते हैं कि भारत किसी भी जटिलता से निपटने की क्षमता रखता है। राष्ट्रीय स्तर की इस सकारात्मक स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर अभियान की भूमिका को भी नकारा नही जा सकता। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप झेलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया निरंतर चलते रहने का एक कारण यह भी है कि प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से युवा वर्ग की क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने की दिशा में काम किया है। आँकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले लगभग चार–पाँच वर्षों में लागू की गईं विभिन्न योजनाओं से प्रदेश के युवा निरंतर लाभान्वित होकर राष्ट्र को मज़बूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

आँकड़ो पर गौर करें तो पिछले चार वर्षों में 74 लाख नई इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई हैं, जिनसे लगभग 2.6 करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला है। प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाई देश में प्रथम स्थान पर है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में नौजवानों का एक ऐसा समूह सामने आया है जो नौकरी पाने के स्थान पर रोज़गार सृजन को प्राथमिकता दे रहा है, जिसका परिणाम यह है कि क़ालीन, पीतल, खिलौने, खेल सामग्री व लकड़ी इत्यादि के उत्पाद व निर्यात में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। इसके चलते वर्तमान समय में देश के निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 4.55 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। उत्तर प्रदेश के मजबूत स्वावलंबी ढाँचे का प्रमुख कारण भी यही है कि पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से युवा पीढ़ी ने निर्यात में अहम भूमिका अदा की है और प्रदेश का युवा देश के साथ–साथ विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा हैं।

"मिशन युवा शक्ति" के तहत विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं के लिए संचालित नौकरी, स्वरोजगार, प्रशिक्षण आदि की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी रूप से लागू किए जाने से बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाया है, जिसका सीधा असर हमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के रूप में देखने को मिलता है। प्रदेश सरकार के "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" एवं "एक जनपद एक उत्पाद" जैसे अभियानों द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को बड़ी संख्या में स्वरोजगार से जोड़ा गया है,जिसके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। प्रदेश भर में कितने ही ऐसे जनपद हैं जिनको एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करते हुए "ओवर्सीज़ ट्रेड प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर" गठित किए गए हैं,जहां पर निर्यातकों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ–साथ आगामी योजनाएं बनाने की दिशा में काम हो रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने "थिंक–ग्लोबल, एक्ट– लोकल" के विचार को अमल में लाकर स्थानीय कौशल को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक योजनाएं आरम्भ की। साथ ही नदियों के तटीय क्षेत्रों में ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने की बात और रक्षा उत्पादों के उत्पादन के लिए 'डिफेंस कॉरिडोर' सरीखी योजनाएं भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के जमीनी प्रयासों का परिणाम है कि गोरखपुर के टेराकोटा शिल्प को 'बौद्धिक संपदा अधिकार' का दर्जा मिला,जिसके बाद इस विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प इकाई की गुणवत्ता में और निखार आया। इससे उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आने वाली दीपावली पर देश चीन में निर्मित देवी–देवताओं की प्रतिमाओं के स्थान पर गोरखपुर टेराकोटा शिल्प की मूर्तियों को प्राथमिकता देगा। इससे प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री की "लोकल के लिए वोकल" वाली अपील का उत्तर प्रदेश में धरातल पर कितना असर हो रहा है।

उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विचार को मजबूती से विस्तार दे रहा है,परंतु अभी स्थिति संतुष्ट होने की भी नही है। आज प्रदेश को आवश्यकता है अपनी विशेषताओं को ब्रांड बनाकर वैश्विक बाज़ार में शामिल करने की। उत्तर प्रदेश की वर्तमान दशा व दिशा के चलते कहा जा सकता है कि प्रदेश के युवाओं में भरपूर ऊर्जा व संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं की ऊर्जा नष्ट न होकर सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्रनिर्माण में सुनिश्चहित हो सके। संख्या के आधार पर देखा जाए तो स्वावलंबी उत्तर प्रदेश में युवाओं की भागीदारी में अभी और वृद्धि की सम्भावनाएँ हैं। भविष्य में प्रदेश सरकार को चाहिए कि युवा वर्ग का सही दिशा में प्रयोग करे जिससे पिछले चार–पाँच वर्षों में विकसित आधारशिला पर खड़ी होने वाली आत्मनिर्भर भारत की मज़बूत इमारत में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का हो।

उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ती स्त्रियां

डॉ. अंशु जोशी
असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएनयू, दिल्ली

आज आधुनिक तकनीक से लैस हमारी जीवनशैली ने पूरे विश्व की संरचना तथा राजनीति पर असर डाला है। कई नए मुद्दे वैश्विक पटल पर सामने आये हैं किन्तु कई ऐसे विषय आज भी प्रासंगिक हैं जो सदियों से महत्वपूर्ण प्रश्न बन समाज के सामने उठते रहे हैं। ऐसा ही एक अत्यंत प्रासंगिक विषय है महिला सशक्तिकरण। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि "आत्मनिर्भर भारत" की संकल्पना में महिलाओं की महती भूमिका है। भारत में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम भारतीय स्त्रियों के बगैर अधूरे हैं।

अब जब भारत आत्मनिर्भर बनने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर वैश्विक मंच पर 'ग्लोबल विद लोकल' तथा 'मेक इन इंडिया' की बात कर रहा है, स्त्री सशक्तिकरण का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत को प्रगति की नयी राह पर आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर तबके का योगदान आवश्यक है। और यहाँ स्त्रियों की भूमिका निश्चित ही निर्णयात्मक हो जाती है। चाहे परिवार हो या समाज या राष्ट्र, भारतीय महिलाएं हर कहीं केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए उन्हें आगे बढ़ाने और सशक्त करने का दायित्व पूरे राष्ट्र पर आ जाता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। वे अपने राज्य में स्त्री सशक्तिकरण के प्रणेता बन कर उभरे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार स्त्रियों के आर्थिक, सामजिक तथा राजनीतिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। साथ ही महिला नेतृत्व को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या उद्यम का। योगी जी ने आधुनिक समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता या जेंडर बायस को समझते हुए नीतिगत स्तर पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, सुरक्षा तथा सम्मान प्रदान करने हेतु ज़मीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया और उन्हें क्रियान्वित कराया है।

पिछड़े तथा गरीब इलाकों तथा तबकों से आनेवाली स्त्रियों को आगे बढ़ाने हेतु उनके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक आयामों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसे भली–भाँति समझते हुए योगी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों को बढ़ाने और उनके भविष्य को उज्ज्वल करने के उद्देश्य से "कन्या सुमंगला योजना" प्रारम्भ की जिसका प्रस्तावित वार्षिक बजट लगभग 1,000 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में महिलाओं के उत्थान हेतु कई प्रावधान किए। महिला एवं बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग 8, 815 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना हेतु लगभग 351 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार के लिए 3,780 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ ही 'शबरी संकल्प योजना' के लिए 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई साथ ही निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 1,263 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया।

बालिकाओं के पोषण कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने लगभग 4,000 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है। किशोरी बालिका योजना के लिए लगभग 156 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। योगी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" तथा "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना" जैसी योजनाओं ने भी राज्य में महिलाओं को मजबूती प्रदान की है।

योगी जी ने केंद्रीय स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं से भी अपने राज्य की स्त्रियों को जोड़ रखा है। 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के माध्यम से महिलाओं के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' के अंतर्गत देश में 16.42 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए गए। "मुद्रा योजना" के माध्यम से 7. 88 करोड़ महिला उद्यमियों को लोन दिया गया। इसी तरह 'स्टैंडअप इंडिया' के माध्यम से 6,895 करोड़ रुपये का कर्ज महिला उद्यमियों को दिया गया।

स्त्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने से वे आकाश छू सकती हैं तथा अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की आर्थिक तरक्की में अभिन्न योगदान दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थन तथा प्रेरणा देने के लिए कई स्तरों पर कार्यशील है क्योंकि उन्हें सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लिए निश्चित रूप से आर्थिक प्रेरणा की आवश्यकता है। योगी

सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में महिला बैंकिंग एजेंटों को नियुक्त करने का फैसला किया, जिन्हें बैंकिंग सखियां भी कहा जाता है। ये महिलाएं गांवों और बैंकों में महिला स्वयं–सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने 'भाग्य लक्ष्मी योजना' जैसी कई योजनाओं को भी लागू किया, जिनके द्वारा स्त्रियों के आर्थिक उत्थान हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है। 'रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष' के तहत विधवाओं की मदद की जा रही है ताकि वे सम्मानपूर्ण तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन यापन कर सकें।

उत्तर प्रदेश महिलाओं पर होने वाले अपराधों में एक अग्रणी राज्य रहा है। स्त्रियों की सुरक्षा न केवल उनकी अस्मिता से जुड़ी है, यह उनकी हर दिन की दिनचर्या, स्वावलम्बन और काम करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ने के लिए उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों में महिला हेल्पलाइन का विस्तार शुरू कर दिया है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 को भी दूसरों के साथ जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए 'सुरक्षित शहर' परियोजना पर भी काम कर रही है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और प्रयागराज में 'सेफ सिटी' परियोजना लागू करने के बाद अब इसे मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और सहारनपुर तक बढ़ाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। स्त्री सुरक्षा योगी जी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह उनके विचारों से जाना जा सकता है। अपने एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि, 'जो लोग नारी गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बेटियों पर बुरी नजर डालेंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। यह लोग सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अपराधियों से पूरी कठोरता से निपटेगी। इनकी दुर्गति तय है'।

स्त्रियों में सुरक्षा, स्वावलम्बन तथा सशक्त होने की भावना को बढ़ावा देने के लिए योगी जी के नेतृत्व में शारदीय नवरात्रि से वासंती नवरात्रि तक चलने वाले 'मिशन शक्ति' को भी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान प्रदेश के समस्त जनपदों, पंचायतों, शहरी निकायों और पुलिस थानों के माध्यम से बच्चियों तथा स्त्रियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण शिविरों तथा उद्यमिता कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही समाज के सामने मिसाल प्रस्तुत करने वाली स्त्रियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'मिशन शक्ति' की शुरुआत हुई। योगी जी ने इस अवसर पर कहा कि, 'सशक्त महिलाएं राज्य को शक्तिशाली बनाती हैं।' योगी जी की प्रेरणा से ही उत्तर प्रदेश राज्य ने महिला सम्मान कोष के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योगी जी ने मिशन शक्ति के उद्घाटन के अवसर पर यह भी कहा कि "शिक्षित समाज ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है।" इसीलिये बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में स्नातक स्तर तक सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए 'अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना' संचालित की जा रही है। वर्ष 2018–19 के बजट में राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ मात्र घूमने–फिरने, मनचाहे कपड़े पहनने या सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने की स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री सशक्तिकरण से तात्पर्य है स्त्रियों के पास निर्णय लेने की शक्ति का होना। प्राचीन भारतीय इतिहास की संस्कृति से जुड़े योगी जी शायद अच्छे से समझते हैं कि स्त्रियों का सशक्तिकरण हमारी मानसिकता पर आधारित है। यदि अपनी मानसिकता से हम स्त्रियों के प्रति कुत्सित विचार और कुरीतियों को निकाल दें, अपने परिवार और समाज के स्तर पर प्रयास करें कि स्त्रियों की शिक्षा, स्वास्थ और आगे बढ़ने के मौकों में हम बाधक नहीं बनेंगे, और यह समझ लें कि स्त्री अपने आप में सबसे सशक्त संरचना है तो स्त्रियों से जुड़े सामजिक भेदभावों और अपराधों से निबटने में हम निश्चित तौर पर सक्षम साबित होंगे।

आज जब हम आत्मनिर्भर भारत संकल्पना को साकार करते हुए भारत को विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं तो इस उद्देश्य की प्राप्ति में स्त्रियों के योगदान को नकार नहीं सकते। सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में श्री योगी ने स्त्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर करने हेतु कई सफल प्रयास किये हैं। निश्चित तौर पर नए भारत के निर्माण में यह प्रयास मील का पत्थर साबित होंगें।

ISSN No. 2581-3528

उत्तम प्रदेश बनता उत्तर प्रदेश

डॉ. नीलम कुमारी
विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी विभाग)
किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलज, सिम्भावली, हापुड़

प्रदेश वही सोच नयी के साथ भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार द्वारा पिछले साढे चार वर्ष के दौरान प्रदेश में किये गए बेमिसाल विकास कार्यों से न केवल भारत में बल्कि विश्व के पटल पर उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश माना जाता था और विभिन्न योजनाओं में उसका स्थान 17 या 27 में स्थान के बीच में था लेकिन आज भारत सरकार की 44 योजनाओं में यूपी नंबर वन पर है। प्रदेश को गुंडाराज से मुक्ति मिली है। अपराधियों की एक हजार करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति जप्त की गई है। पुलिस ने 135 अपराधियों का एनकाउंटर किया है और बड़ी संख्या में गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई की गई है। आज प्रदेश में भयमुक्त माहौल है। आज महिलाएं रात में घर से निकलने से नहीं डरती हैं। प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सहित चार एक्सप्रेस–वे का निर्माण हो रहा है और इनका पूरा होने से प्रदेश की तस्वीर ही बदल जाएगी। प्रदेश में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। नए उद्योगों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सभी भर्तियो में पारदर्शिता बरती गई है। ऐसे में न केवल भारत मे बल्कि विश्व में भी उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में मात्र अल्पकाल जो बदलाव हुआ है वह किसी अन्य प्रदेश में नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार ने अपनी दूरदर्शी योजनाएं तैयार कर उन्हें धरातल पर उतारने का जो उत्कृष्ट कार्य किया है वह वास्तव में प्रसंशनीय है। बीते 54 माह में राज्य के माथे से बीमारू राज्य का धब्बा हट गया और समृद्धि शीलता का टीका लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की प्रंशसा करते हुए कहा है कि 'आज उत्तर प्रदेश पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है' प्रदेश की सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है और सब के लिए विकास के दरवाजे खोलना है। जो लोग योगी जी को नजदीक से जानते हैं उन्हें पता है कि वह अपने काम में कितने कुशल है उन्होंने सत्ता संभालते ही अपने सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की बात कही जो जनता के प्रति जवाबदेही की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है इसी तरह उन्होंने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए। साफ है कि अपनी टीम के बूते योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के कार्य में जुट गए हैं।इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ष्एक भारत श्रेष्ठ भारतष के सपने को भी गति भी मिलेगी ।वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास के इतने कार्य हुए हैं कि उन्हें एक लेख में समाहित कठिन है परंतु **'प्रत्यक्ष कि प्रमाणम'** जगमग गांव, लहलहाते खेत, निश्चिंत महिलाएं, उत्साही युवा, उत्सुक उद्यमी, चमचमाती सड़कें स्वयं ही विकास की कहानी कहते हैं। वर्तमान सरकार की दृढ़ता, दूरदर्शिता, सजग प्रबंधन और संवेदनशीलता से माहौल इतना बदल गया है कि उत्तर प्रदेश उद्योगपतियों, पूंजी निवेशको व कॉर्पोरेट सेक्टर का सर्वप्रिय राज्य बन गया है। लोक कल्याण के लिए पूर्णरूपेण समर्पित इस सरकार पर यह सूक्ति सर्वथा चरितार्थ होती है कि

काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः

अर्थात समय से प्रारंभ की गई नीतियां सफल होती है। यह सारी नीतियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और उनके निर्णय लेने की क्षमता के कारण ही साकार हो पायी है। पहले सरकारों में गुंडाराज व भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भाई भतीजावाद से जनता दुखी लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने से आज उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के लोगों की धारणा बदली है। सुरक्षा व सुशासन होने से बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। कारोबारी सुगमता

ISSN No. 2581-3528

में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान नंबर पर आ गया है। चाहे योगी सरकार के द्वारा किसान हित को सर्वोपरि रखते हुए गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड रुपए का भुगतान करने की बात हो या हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण कर संस्कृति के सत्कार की बात हो, चाहे मेट्रो कॉरपोरेशन को मिली पहली बोगी पर काम शुरू करने की बात हो या शिक्षा के क्षेत्र में 2022 तक 7 नए विश्वविद्यालय और पांच महाविद्यालय बनाने का कार्य हो, चाहे देश और दुनिया में बेजोड़ कोरोना प्रबंधन को सराहे जाने की बात हो या महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मिशन शक्ति और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देकर महिलाओ को सशक्त करने की बात हो, चाहे एक जिला एक उत्पाद द्वारा परंपरागत उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो या फिर नोएडा में फ़िल्म सिटी का निर्माण कर लाखो लोगो के सपनो को साकार करते हुए रोजगार सृजन करने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने की बात हो या प्रदेश में भयमुक्त माहौल बनाने की बात हो चाहे चुनोतियों में अवसर तलाशने की बात हो या विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो या खेलो को बढ़ावा देने की बात हो चाहे मुफ्त टिके मुफ्त राशन की बात हो या फिर उज्ज्वला योजना तहत करोड़ो गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की बात हो चाहे बेघरों को घर देने की बात को या जन सामान्य की बुनियादी सुविधाएं देने की बात हो चाहे बात स्वच्छता मिशन की हो या गाँव–गाँव, शहर–शहर विकास की बयार हो चाहे वनों का सौन्दर्य करण हो या गोवंश का संरक्षण हो चाहे सारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण हो या उत्तर प्रदेश के वर्ष 2021–22 का सर्वसमावेशी, सर्वहितैषी बजट द्वार उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो सभी कार्यों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार का सुरक्षा व सुशासन का मॉडल दुनिया भर में सराहा जा रहा है। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा व प्रशासन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से देश और दुनिया की धारणा को बदला है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पेशेवर माफिया सत्ता के संरक्षण में अराजकता और भय फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन गई थी और 2012 से 2017 के बीच तीसरे दिन औसतन एक बड़ा दंगा होता था। लेकिन साढे चार वर्षों में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ वहीं दूसरी ओर कारोबार में सुगमता में लंबी छलांग लगाई है जो उत्तर प्रदेश 2016 में कारोबार क्षमता में 14 वे स्थान पर था वही उत्तर प्रदेश आज द्वितिय स्थान पर है वहीं वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश देश की छोटी अर्थव्यवस्था था लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में से है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरसः लागू करने के लिए अपनी योजना तैयार कर ली है। इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है, तभी हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि–

प्रधानमंत्री जी का विज़न हो रहा साकार।
काम दमदार योगी सरकार।।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश।
बना रही योगी सरकार।।

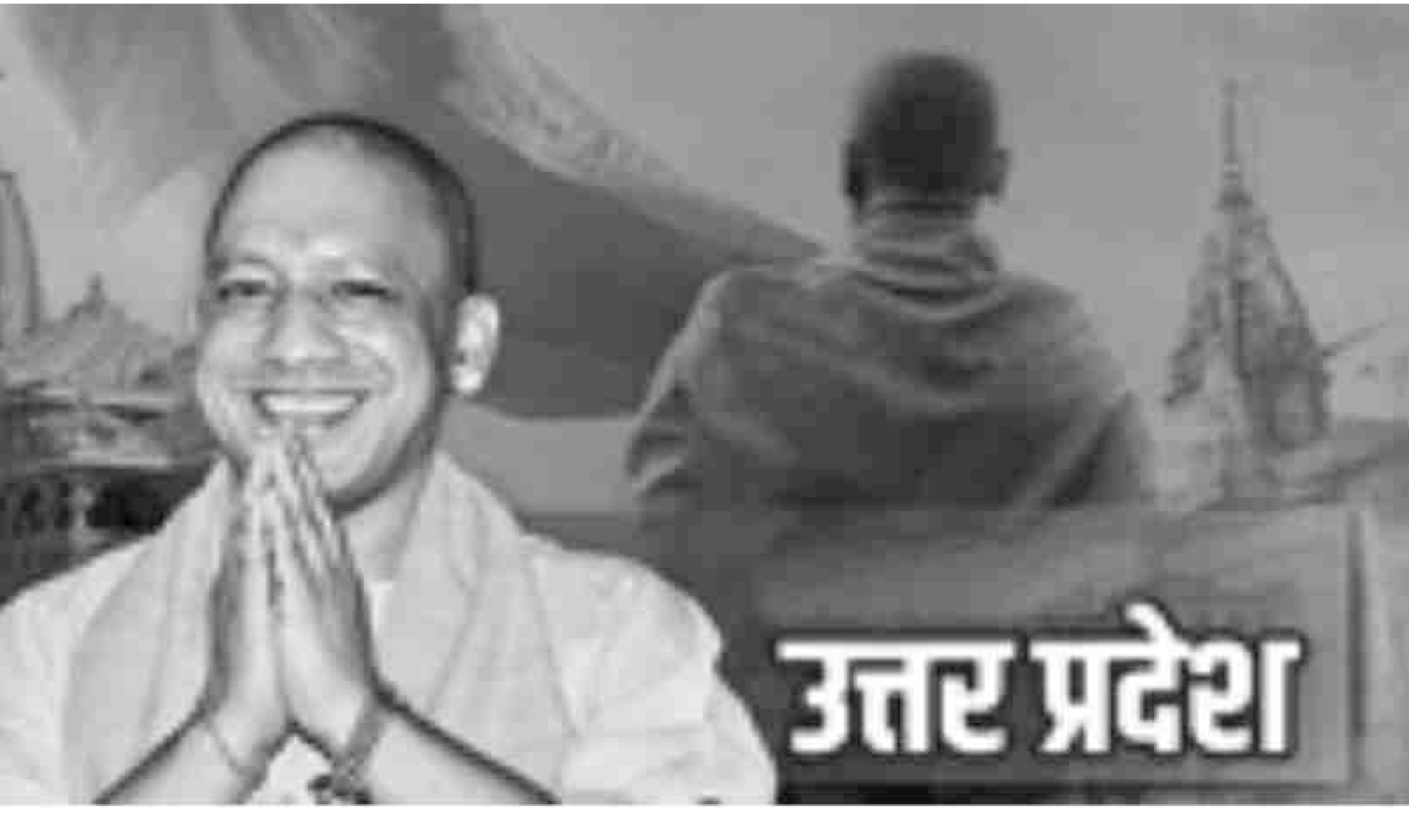

ISSN No. 2581-3528

आत्मनिर्भरता को पंख लगाता विदेशी निवेश

नेहा कक्कड़
एम. फिल ,पत्रकारिता एवं जनसंचार
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कोरोना काल और सोशल मीडिया मार्केटिंग ने जैसे कारोबार का तरीका और असर दोनों ही बदल कर रख दिया है जिसका प्रभाव प्रोडक्शन से लेकर, मार्केटिंग तक देखा जा सकता है। जहाँ एक ओर कोरोना महामारी की चपेट में समूचा विश्व आया वहीं टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म ने मजबूत स्तम्भ की तरह साथ भी निभाया। कोरोना के संकट को भांपते हुए आर्थिक मंदी से मुकाबला करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की जिससे की देशवासी आत्मनिर्भरता की डगर पर चलें। इस अभियान के अंतर्गत रोजगार व स्वरोजगार पर अधिक ध्यान दिया गया, साथ ही आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी घोषित किया, जो देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत था।

आज समूचा विश्व खुद को कोविड व आर्थिक मंदी से बचने के लिए आत्मनिर्भर हो, निर्यात पर बल दे रहा है जो समय और परिस्थिति की मांग में शामिल हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा भी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दृष्टि से विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर बल दिया गया क्योकि जो भी कंपनी भारत में निवेश करेगी, वो रोजगार के अवसर तो लाएगी ही,युवाओं को तकनिकी, प्रौद्योगिकी रूप से प्रशिक्षित भी करेगी, जिसके परिणाम स्वरुप नई तकनीक से प्रशिक्षित वर्ग भविष्य में आत्मनिर्भर बने इसकी सम्भावना भी बढ़ेगी। कोरोना काल में चीन का अन्य देशो से आर्थिक व्यवहार का बदलना, जिसका प्रत्यक्ष फायदा भारत को होता दिख रहा है, क्योकि चीन के अन्तर्राष्ट्रीय छवि में उतार चढाव के कारण विश्व की कई कंपनियों ने चीन से बाहर निकल भारत में निवेश की और रुख किया हैं। भारत ने भी विदेशी कंपनियों का खुले मन से स्वागत किया और विदेशी निवेश के लिए सुलभता सुनिश्चित की ताकि देश कोविड में हुई आर्थिक मंदी, बेरोजगारी से लड़ सके।

आत्मनिर्भर भारत को विदेशी निवेश ने कैसे पंख लगाए? इस विषय पर बात करने से पूर्व भारत में विदेशी निवेश की मुख्य प्रवृतियों को समझना अत्यंत आवश्यक है।

"विदेशी निवेश" अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों में तथा किसी एलएलपी की पूंजी में प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया निवेश।

[redacted]प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)" अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा गैर–सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटि के 10 प्रतिशत तक अथवा उससे अधिक किया गया निवेश।

"विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)" अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटि के जरिए पूंजीगत लिखतों में 10 प्रतिशत से अनधिक किया गया निवेश अथवा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा जारी पूंजीगत लिखतों की प्रत्येक शृंखला में 10 प्रतिशत से अनधिक मात्रा तक किया गया निवेश।

21 जून 2021 को अंकटाड (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report), 2021 के अनुसार भारत ने साल 2020 के दौरान 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि एफडीआई हासिल किया है। इसके साथ ही यह एफडीआई हासिल करने वाला दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश बन गया है। कोविड–19 की दूसरी लहर ने देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल्स ने मध्यम अवधि के लिए उम्मीद की किरण को बनाए रखा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई 2020 में 27 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट–2021 के अनुसार महामारी की वजह से वैश्विक एफडीआई प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह 2021 में 35 प्रतिशत गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर रह गया, जो कि एक साल पहले की अवधी में डेढ़ लाख करोड़ डॉलर था। यूएन द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट 2021के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2021 में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। इन आकड़ो से ये स्पष्ट होता है की एक ओर रोजगार तो बढ़ेगा ही, वहीं दूसरी ओर भारत के स्किल्ड पापुलेशन में भी बढ़ोतरी होगी। आत्मनिर्भर भारत और 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा के तहत केंद्र के साथ ही राज्यों में निवेश आकर्षित करने की मुहिम चली जिसमे

कई राज्य इस दिशा में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

कोई भी विदेशी निवेशक, निवेश के लिए कुछ प्रमुख बिन्दुओ पर विचार करता है जैसे कि क्या यहां उनके माल का बाजार है? कोई देश निर्यात केंद्र की दृष्टि से कैसा है? पारदर्शिता एवं कारोबारी सुगमता का स्तर क्या है? वैश्विक महामारी COVID–19 के बाद भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए व् 'भारतीय उद्योग परिसंघ' (Confederation of Indian Industry&CII) ने भारत के व्यापार परिदृश्य को आसान बनाने के लिये प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक उपायों की पहचान की है ताकि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सके।

विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट के अनुसार भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है। सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत पिछले 5 वर्षों (वर्ष 2014–19) में 'व्यापार सुगमता सूचकांक' में अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों का उल्लेखनीय सुधार करने में सफल रहा है। जमीन, बिजली, पानी आदि में समस्या तो नहीं होगी। किसी भी तरह की वाद की स्थिति में वहां के कानून के शासन की हालत कैसी है। काम के लिए मनोनुकूल मानव संसाधन हैं क्या। इन सभी के साथ वे यह भी देखते हैं कि वहां का श्रम कानून कैसा है और श्रम की लागत कैसी है। संयोग से भारत में ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में हैं बस आवश्यकता हैं इन सभी चीजों के समन्वय और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के मानकों के प्रचार की,और आगे भविष्य में भी होगी ताकि विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। ये भारतवासियों की इच्छाशक्ति का परिचय ही था कि कोविड महामारी के दौरान भी आत्मनिर्भरता की डोर को थामे पीपीई किट, मास्क बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार द्वारा सशक्त भारत की अवधारणा के तहत विदेशी कंपनियों के भारत आने का मार्ग प्रशस्त किया गया हैं साथ ही साथ स्वरोजगार से उत्पादित माल को विदेश में निर्यात करने का मार्ग भी सुलभ किया हैं। आत्मनिर्भर भारत को पंख देने के लिए कई राज्यों ने भी अपने स्तर पर कोशिशें कीं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक प्रमुख अभियान 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई योजनाए एवं नीतियां सफल नज़र आ रही है जो भविष्य में निश्चित ही आत्मनिर्भर भारत की ओर एक नए आयाम स्थापित करेगी।

केशव संवाद

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े। एवं केशव संवाद को सोशल मीडिया पर FOLLOW करें

Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

FACEBOOK

ISSN No. 2581-3528

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और किसान

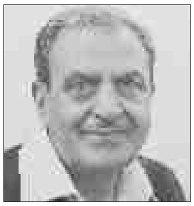

डॉ. यशवीर सिंह
पूर्व अध्यक्ष, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार

उत्तर प्रदेश की जलवायु, नदियां, पानी की उपलब्धता हिंदुस्तान ही नही दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए पूरी दुनिया में गंगा–यमुना का दोआबा कृषि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता का आंकलन किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान को अन्न खिलाने की क्षमता है। कृषि क्षेत्र की प्रगति और किसान को उसकी मेहनत का पूरा न्याय मिले तो वह और ज्यादा पैदावार बढ़ा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी योजनाएं जैसे मिट्टी की जाँच, कृषि कौशल योजना, सिंचाई योजना, कर्ज की उपलब्धता, ई–कृषि मंडी, जैविक खेती नदियों को जोड़ना आदि योजनाओं से उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नही बल्कि सरयलस स्टेट बन गया है केवल दालों और तिलहन को छोड़कर गन्ना और चीनी के उत्पादन में देश में सबसे आगे है।

पिछले पांच वर्षो में 1200 करोड़ श्रम दिवसों का सर्जन कर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं आवास योजना का कार्य किया गया। सड़कों का जाल की तरह निर्माण और नदियों की सफाई तथा उन्हें नहरों द्वारा जोड़ने का कार्य भूजल स्तर को ठीक रखने के लिए किया गया आज भी देश की 60 प्रतिशत कृषि इंद्र देवता यानि वर्षा पर निर्भर है जो सीधे तौर पर फसलो के उत्पादन को प्रभावित करती है जिससे किसान का हित प्रभावित होता है। कृषि योग्य भूमि को आवश्यकता अनुसार पानी पहुचाकर फसल बढ़ोत्तरी की गई है। इसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रीप सिंचाई योजन का भी जाल बिछाया जा रहा है तथा ट्यूबेल व बैलो का खास तौर पर छोटे किसानों को सोलर पम्प द्वारा सिंचाई करने का इंतजाम किया है।

देश और प्रदेश की आत्म निर्भरता खेती पर तथा उससे जुड़े हुए उद्योगों पर ज्यादा निर्भर करती है। कृषि कौशल योजना के द्वारा युवा किसानों को कौशल प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कौशल परीक्षण के बाद किसानों को सस्ते दर पर ब्याज पर कर्ज देकर उनको आत्म निर्भर बनाया जा रहा है। किसी भी कार्य का व्यवसायिक तथा व्यवसायिक प्ररीक्षण उस कार्य की प्रगती का संभावनाओ को कई गुना बढ़ा देता है।

कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुशल कामगार भी तैयार किये जा रहे है उसका भी उत्पादन में वृद्धि का लाभ प्रदेश और देश को मिल रहा है। अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार तथा आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी है। गोकुल मिशन के अंतर्गत, बेहतर प्रशिक्षण द्वारा 40 प्रतिशत स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण किया गया है इससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। डेयरी विकास के द्वारा गोकुल ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाया गया है तथा पशुओ में आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए बड़े पैमाने में टीकाकरण की योजना चला कर बीमारियों पर नियंत्रण पाया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्यों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसानों को देकर उनको लाभ पहुंचाया गया है जिसका नतीजा यह है कि पिछले सालो में रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई है। किसानों को इसमें न्याय के साथ साथ अधिक उत्पादन बढ़ाने का भी प्रोत्साहन मिला है यह योजना उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को लाभ पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी किसानों को आपदाओं से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा किसानों का प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान एक सीमा तक किया गया जिससे मध्यम तथा छोटे किसानों को अधिक लाभ हुआ। बागवानी क्षेत्र में भी फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। ई मंडी योजना के अंतर्गत गेहूं धान चावल, चना सरसों, आदि फसलो की ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था लागू होने से सारी मंडियों में पारदर्शिता तथा किसानों को सही दाम मिलना शुरू हो गया है। ई मंडी पोर्टल पर फसलो का दाम व बिक्री व्यवस्था की जानकारी किसानों को उपलब्ध हो जाती है। तथा बिक्री का पैसा भी सीधा किसानों के खाते में आ जाता है। यह योजना किसानो को शोषण से बचा रही है।

किसानों द्वारा मजबूरी में अपना उत्पाद बेचने को हतोत्साहित करने और अपने उत्पादन को भण्डारो में रख कर रसीद प्राप्त करके उस रसीद पर बैंको से रियायती ब्याज का लाभ उठा सकते है। यह योजना किसानो के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। देश में इसके चलते भंडार ग्रहों की मांग बढ़ रही है।

इस क्षेत्र में सार्वजानिक के साथ निजी निवेश भी बढ़ रहा है कृषि की विकास दर को रफ्तार देने के लिय्हे निजी क्षेत्र का निवेश बहुत आवश्यक है कृषि क्षेत्र में पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स पालन आज देश को कृषि अर्थ व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे है तथा छोटे किसानो के लिए यह अतिरिक्त आय का साधन बनते जा रहे है। सरकार के प्रोत्साहन से तथा सस्ते ब्याज पर धन उपलब्ध होने से यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानों को बीजो का वितरण खास तौर पर दालो और तिलहन की फसल का वितरण किया जा रहा है जिसे इन फसलो की उत्पादन बढ़ा है। लेकिन फिर भी दालों और तिलहन की पैदावार में आत्मनिर्भर नही तथा बड़े पैमाने पर

विदेशों से आयात किया जा रहा है।

खाद्य तेलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है जिसके लिए तिलहन और तेल मिशन कार्य क्रम शुरू किया गया है।

आज देश के ज्यदातर राज्य गेहूं, धान चावल कपास, गन्ना आदि में अधिक पैदावार कर रहे है। यदि किसानो ने 4 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादकता बढ़ा दी तो सरकारों के पास अनाज रखने की समस्या बन कर खड़ी हो जायेगी चूँकि गेहूं और चावल और चीनी तो पहले ही एक वर्ष की खपत के बराबर सरपलस है।

डब्लूएचओ की प्रतिबद्धता के चलते सरकार एक सीमा से ज्यादा न तो किसानो को सब्सिडी दे सकती तथा निर्यात का कोटा भी नहीं बढ़ पा रहा है जिसके चलते निर्यात की संभावना भी बहुत ज्यादा नहीं है सरपलस राज्यों के सामने यह बड़ी चुनौती है क्योंकि सेंट्रल पुल में बहुत ज्यादा खरीद की गुंजाईस नही है।

बागवानी क्षेत्र में फलो और सब्जियों के विकास के लिए आम, केला, सेब, सुगन्धित फूल तथा फसलो के उत्पादन में हमने बहुत ऊँचा लक्ष्य हासिल किया है यहां तक कि फल और सब्जियों का उत्पादन आनाज के उत्पादन से आगे निकल गया है ^ देश की आर्थिक वृद्धि के चलते समाज के मध्यम वर्ग में फल और सब्जियों के खाने का प्रतिशत बढ़ गया है जिससे फल और सब्जियों की मांग पिछले वर्षों में 40 प्रतिशत बढ़ी है।

आज देश में नई—नई फसल जैसे मशरूम, डूरेगान फल जैसी फसलो की पैदावार तथा फसल एरिया बढ़ रहा है जो कि कृषि की डाइवर्सिटी के लिए आवश्यक है। सरकारों की कोशिश है कि गेहूं, चावल के बजाय इन नई फसलों पर किसान ज्यादा ध्यान दे।

किसानों के लिए आत्मनिर्भरता के आलावा सबसे बड़ी समस्या किसान की जोत पीढ़ी दर पीढ़ी घटती जा रही है। आज देश में मध्यम एवं लघु जोत के किसान की संख्या 86 प्रतिशत पहुंच गई है जिसमे 38 फीसदी लघु किसान हो गया इसके पास बचने के लिए अधिक नही है अतः यह अपना गुजारा पशुपालन तथा दुसरे धंधो से कर रहा है और यह संख्या हर योजना में बढ़ती जा रही है। इसी छोटे तथा लघु किसानों को आत्म निर्भर बनाने के लिए सरकार ने पीएम किसान योजना चलाई इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 6000 रुपया प्रति किसान उसके खाते में सहायता पहुंच रही है। यह योजना किसान के लिए सामान जनक जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही है। ताकि वह समय पर खाद, बीज खरीद कर अपनी कृषि की आवश्यकता पूरी कर सके चूंकि उसके पास पैदावार में अधिक कुछ भी नही है और वह साहूकारों के कर्ज से बच सके।

ग्रामीण सड़कों का विस्तार भी कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुआ है यह देखते हुए सरकार ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा रही है किसान के हित में बनाई गयी योजना तथा टेक्नोलॉजी के जरिये 21वीं सदी इस देश में किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक रही जिसका असर हम कोविड—19 के चलते देख चुके है। हमारे भरे अन्न के भण्डारों ने किसी को भूखा नही रहने दिया। सरकारों ने मुफ्त में गरीबों को गेहूं, चावल, दाल का वितरण कर दुनिया को आत्म निर्भरता का उदहारण पेश किया।

ISSN No. 2581-3528

प्रशासनिक व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में मील का पत्थर बना उत्तरप्रदेश

अनीता चौधरी
पत्रकार

उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था का डंका न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में बज रहा है। मौजूदा बीजेपी की सरकार ने अपराधियों और माफियों पर जबरदस्त नकेल कसा है। अपराधीकरण पर नियंत्रण को लेकर अगर उत्तरप्रदेश की स्थिति पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानि एन.सी. आर.बी. के आंकड़ों पर भी जाए तो आंकड़े बता रहे है कि अपराध नियंत्रण के मामले में उत्तरप्रदेश की योगी सरकार अपराधियों और कानून की धज्जियाँ उड़ाने वालों पर भारी है। अगर अपराधियों और माफियों पर करवाई को लेकर भी अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। पिछले 4 सालों के दौरान न सिर्फ अपराध में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है बल्कि अपराधी तत्वों पर प्रभावी नकेल भी कसी गयी है। उत्तरप्रदेश में जिस तरह से सरकार कानून–व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण पर रणनीति के तहद करवाई कर रही है ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ही यह नतीजा है कि प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में अपराधों में गिरावट का सिलसिला निरन्तर जारी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में घटित अपराधों के तुलनात्मक आकड़ों के अनुसार मौजूदा सरकार के कार्यकाल में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर अलग अलग पॉलिसी और रणनीति के तहद करवाई की जो काफी सफल रहा चाहे वो ऑपरेशन लंगड़ा हो या रोमियो स्क्वॉड, या हेल्पलाइन नंबर 112 पर उत्तर प्रदेश को अपराधमुक्त या गुंडाराज की सोच से बहार निकालने के लिए जिस तरह से बीजेपी की मौजूदा सरकार प्रयासरत है और राज्य में संगठित अपराध और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए कहर बन कर टूट रही है वो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है।

ISSN No. 2581-3528

उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़े

♦ **डकैती के मामलों में 2016 की तुलना में 2020 में 74.50 तथा 2012 की तुलना में 74.67 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।**

♦ **लूट के मामलों में 2016 और 2020 की तुलना करें तो 65.29 प्रतिशत तथा 2012 की तुलना में 54.25 प्रतिशत की गिरावट आई है।**

♦ **हत्या के मामलों में 2016 की तुलना में इस साल 26.43 तथा 2012 के सापेक्ष 29.74 प्रतिशत की कमी आई।**

♦ **फिरौती के लिए अपराध के मामलों में वर्ष 2016 की तुलना में 2020 में 54.55 तथा 2012 की तुलना में 64.29 प्रतिशत की कमी आई है।**

♦ **रोड होल्ड अप के मामलों में यह गिरावट 100 प्रतिशत रही। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2020 तक रोड होल्ड अप की एक भी वारदात नहीं हुई है।**

♦ **बलात्कार के प्रकरण में 2013 और 2020 की तुलना करें तो 25.94 प्रतिशत, 2016 की तुलना में 38.74 प्रतिशत तथा वर्ष 2019 की तुलना में 28.13 प्रतिशत की कमी आई है।**

अगर माफियों या अपराधियों पर करवाई की बात करें तो मुठभेड़ की संख्या भले बढ़ी लेकिन अपराध और अपराधियों में भारी गिरावट आयी। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2017 से लेकर अब तक राज्य भर में कुल 8559 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 3349 अपराधियों को गोली मारकर घायल किया गया है। इन मुठभेड़ों में अब तक 146 अपराधियों की मौत भी हुई है जबकि इस दौरान 13 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं जबकि करीब 12 सौ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। मुठभेड़ों के दौरान 18 हज़ार से भी ज़्यादा अपराधी गिरफ़्तार भी हुए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं की अवैध संपत्ति पर जबरदस्त कार्रवाई की है। यूपी पुलिस ने माफियाओं और गैंगस्टरों की कमर तोड़ने और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में उनकी 1800 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। अप्रैल 2017 से शुरू हुये इस अभियान के तहत गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 13,801 मामले दर्ज किए गए और 43,294 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 630 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि रासुका के तहत कार्रवाई की गयी। इनमें पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद, बसपा विधायक और कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी, सुंदर भाटी, ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, विकास मिश्रा सभी शामिल हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अबतक उसके गिरोह के 89 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और 325 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर ध्वस्त कर दिया गया है तथा उसके द्वारा कब्जा की गई जमीन को भी सरकार के निर्देश पर पुलिस ने जबरदस्ती कब्जे से मुक्त करा लिया है। साथ ही इसके गिरोह के 60 सदस्यों के हथियारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इसी तरह बांदा जेल में बंद माफिया और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुये पुलिस ने 194 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की और गिरोह के 244 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। अंसारी गिरोह के 122 सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं , जबकि 158 को गिरफ्तार भी किया गया।

इसी तरह वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद पश्चिम यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुये पुलिस ने 63 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की और उसके गिरोह के सदस्यों के चार हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए। बलिया जेल में बंद कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुये पुलिस ने 17.91 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है या उसे ध्वस्त किया है। लखनऊ के ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर के संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, गौतम बौद्ध नगर के सुंदर भाटी और सिंहराज भाटी जैसे कुख्यात अपराधियों के मामले में पुलिस ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा जिस कारण इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।

जिस तरह से प्रशासन को दुरुस्त और कानून व्यवस्था को चुस्त करने के लिए उत्तरप्रदेश की योगी सरकार अपराधियों. पर कहर बनी हुयी है ये कहना गलत नहीं होगा की अगर यही रफ़्तार आगे भी बानी रही तो उत्तरप्रदेश अपराध ही नहीं बल्कि अपराधी मुक्त की राह पर है।

ISSN No. 2581-3528

चुनौतियों को अवसर में बदलता उत्तर प्रदेश

डॉ. शशि शर्मा
विभागाध्यक्ष राजनीतिशास्त्र
केशव मारवाड़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज पिलखुवा, हापुड़

उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल कहा जाता है यही वह प्रदेश है जिससे उस संस्कृति का उद्भव एवं विकास हुआ है जिसे हम भारतीय संस्कृति के रूप में जानते हैं। संपूर्ण भारत की झलक भारत के लघु रूप उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है धर्म का भारतीय संस्कृति के मूल आधार स्तंभ भगवान राम एवं कृष्ण की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश की है सम्राट भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है कि जन्म स्थली भी यही प्रदेश है हिंदी साहित्य के सूर्य और शशि महाकवि सूरदास तथा तुलसीदास का जन्म भी इसी प्रदेश मैं हुआ महारानी लक्ष्मी बाई जैसी वीरांगना की गौरव गाथा इस प्रदेश से जुड़ी है यह प्रदेश बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रमुख कार्य क्षेत्र भी रहा है प्रदेश में विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता है।

भारत की धर्मनिरपेक्ष राजनीति का केंद्र प्रयागराज भी इसी प्रदेश में है इस प्रकार सांप्रदायिक तथा धर्मनिरपेक्ष राजनीति की जननी इस प्रदेश की धरा को माना जाता है इसलिए मैं केवल स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रीय राजनीति में उतर प्रदेश की विशिष्ट भूमिका रही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा तथा उनके मार्गदर्शन में योगी सरकार ने जिस तरह विकास की गति को आगे बढ़ाया उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की 44 योजनाओं में अग्रणी है विकास का यह रिकॉर्ड भी संकट की ऐसी घड़ी में कायम हुआ है जब पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझता रहा पर योगी जी की दूर दृष्टि एवं विकास की अवधारणा का ही फल है कि उत्तर प्रदेश में कोविड 19 पर नियंत्रण का समुचित प्रबंधन करते हुए उन्होंने इस आपदा को भी अवसर बदल दिया कोविड की चैन टूटतीं रही और रोजगार के साथ ही विकास की कड़ियां जुड़ती रही। आर्थिक गतिविधियों ने भी तेजी पकड़ी प्रदेश में बेरोजगारी की दर जहां पर 2017 में 17.5 प्रतिशत थी वहीं 28 फरवरी 2021 को घट कर 4.1 प्रतिशत रह गई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान भी स्थापित हुए योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रशंसा हुई ही विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ ने भी सराहना की।

महामारी के दौरान अन्य प्रदेशों से वापस आए 40 लाख कामगारों/श्रमिकों की इस स्किल मैपिंग कराकर उनके गांव में ही रोजगार देने का बड़ा कार्य किया। योगी सरकार के कार्यकाल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना विकास हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। कुल 771 कोविड चिकित्सालय क्रियाशील किए गए। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में 234 टेस्टिंग लैव स्थापित की गई सर्वाधिक 1,75 लाख कोविड–बेड उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे रहा। इसके बाद वैक्सीन का बड़ा कार्य भी सामने था प्रदेश में अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करके उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बन गया।

योगी सरकार ने आपदा काल में निधि किसानों का हित सर्वोपरि रखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 241 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 27286 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का भी गठन किया गया गौ पालन एवं संरक्षण में भी प्रदेश अग्रणी है। पानी की समस्या से निदान दिलाने के लिए सरकार ने प्रदेश में वर्षों से लाभांवित 11वृहद सिंचाई परियोजनाएं को पूर्ण करके निःशुल्क बोरिंग गहरी एवं मध्यम बोरिंग आदि सिचाई माध्यमों से भी सिंचन क्षमता अर्जित की गई जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की 30, हजार ग्राम पंचायतों को हर घर नल योजना से भी जोड़ा गया।

महिलाओं को मजबूत व सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी जिसका उन्होंने डट कर सामना किया योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाएं अब भय और असुरक्षा के माहौल से उबर कर गरिमामयी जीवनयापन कर रही है। एंटी रोमियो एक्वायर्ड का गठन करते हुए छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम कदम उठाए हैं मिशन शक्ति के जरिए सरकार महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। 218 नए फास्टैक कोर्ट दे महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई है हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए वास टॉक सेंटर स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ता साइबर अपराध और डकैती के मामले तथा दुष्कर्म के मामले उत्तर प्रदेश के विकास में बड़ी चुनौती साबित हुई है सड़क का सुलभ एवं सरल ना होना युवाओं को रोजगार न मिलाना बड़ी समस्या थी इसका सरकार ने डटकर सामना किया।

उपयुक्त सभी चुनौतियों से उत्तर प्रदेश सशक्त हुआ है जैसा कि एक कहावत है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है उत्तर प्रदेश जिसकी स्थिति विभिन्न भूतपूर्व सरकारों द्वारा कीचड़ सा सदृश्य कर दिया था 2014 के बाद से वास्तविक रूप में कमल खिलता हुआ स्पष्ट हो रहा है वर्तमान में राज्य में चंहु मुखी उन्नति दिखाई दे रही है और सभी चुनौतियों का डटकर सामना करते व उन पर विजय प्राप्त की है।

ISSN No. 2581-3528

-मुक्ता शर्मा, मेरठ
मौलिक एवं स्वरचित रचना

बन रहा है, और संवर रहा है।
प्रति दिन अब, निखर रहा है।
मेरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश।

गंगा और यमुना से यह पोषित,
भारत मां का हृदय सुशोभित।
वाल्मीकि और व्यास की भूमि।
रूप मनोहर करता है मोहित।
मेधाओं का सदा नगर रहा है
मेरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश।

रामऔर कृष्ण की, पावन धरती,
गौतमबुद्ध की यह तपस्थली है।
मंदिर बनेगा अब रामलला का,
न जाने कब की आस फली है।
एक प्रदीप्त दिनकर रहा है।
मेरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश।

वीरोचित इसका इतिहास रहा है,
हर एक पहलू यहां खास रहा है।
स्वतंत्रता के समर में दी आहुतियां,
था अविस्मरणीय बलिदान यहां का।
प्राणोत्सर्ग में भी मुखर रहा है।
मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश।

एक समय, ऐसा भी था आया,
चारों दिशाओं में अंधेरा छाया।
अब फिर से गौरव पाया है।
इंसान आज सुशासन पाया।
बदल रहा है अब संभल रहा है।
मेरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश।

अब निशि दिवस उन्नति अग्रसर।
उत्तर प्रदेश बन रहा आत्मनिर्भर।
सुरक्षा और सम्मान है सबको,
रोज रोज यह बन रहा है बेहतर।
नित नए प्रतिमान गढ़ रहा है
मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश।

मार्ग सभी हैं फर्राटा भर रहे।
आज सुरक्षित हैं मां बहनें।
चिकित्सा और रोजगार मिला है।
जन योजनाओं, के क्या कहने।
उन्नति के सोपान चढ़ रहा है।
मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश।

बन रहा है और संवर रहा है।
प्रतिदिन ही अब निखर रहा है।
मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश।

दिल में
हिंदुस्तान
देश को करें रोशन
मेक इन इंडिया
के साथ
SURYA
MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES
आत्मनिर्भर भारत की पहचान
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | Toll Free No.: 1800 102 5657

सफाई, दवाई और कड़ाई
जीतेंगे कोरोना से लड़ाई

क्या आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई?

45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक टीकाकरण अवश्य करवाएं

घर पर रहें, सुरक्षित रहें

दो गज़ की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करें

नियमित योग/प्राणायाम करें एवं काढ़े का सेवन करें

हाथों को बार-बार साबुन या सैनिटाईजर से साफ रखें

18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए भी 1 मई, 2021 से टीकाकरण शुरू हुआ

घबराने की नहीं है बात
सरकार खड़ी है साथ

हेल्पलाइन नं.
104
कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए www.cowin.gov.in या आरोग्य सेतु एप पर रजिस्टर करें

#Unite2FightCorona

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

सफाई, दवाई और कड़ाई
जीतेंगे कोरोना से लड़ाई
जब जरूरी हो
तभी बाहर निकलें
बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर
बीमारियों से ग्रसित लोग घर से न निकलें
मास्क जरूर लगायें
दो गज़ की दूरी का पालन करें
हाथों को बार-बार साबुन या
सैनिटाईजर से साफ रखें
अपनी बारी आने पर टीकाकरण कराएँ
कोरोना की जाँच और उपचार
सरकारी अस्पतालों में
निःशुल्क है
घबराने की
नहीं है बात
सरकार
खड़ी है साथ
सफाई भी
दवाई भी
कड़ाई भी
हेल्पलाइन नं.
104
कोविड-19 का टीका
लगवाने के लिए
www.cowin.gov.in या
आरोग्य सेतु एप पर
रजिस्टर करें
#Unite2FightCorona
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश